मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 38 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 17 – 23 सितंबर 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

शिक्षक दिवस और शिक्षा जगत की चुनौतियां 7

मोदी सरकार और उसकी विनाशकारी नीतियों से मुक्ति के अभियान का समय.....9

तिरुपति में आंध्रप्रदेश प्रचार बस यात्रा का समापन

2024 में भाजपा को मात देने का आह्वान

राम नरसिम्हा राव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आंध्रप्रदेश राज्य परिषद ने 17 अगस्त 2023 को विशाखापट्नम स्टील प्लांट से जो प्रचार बस यात्रा शुरू की थी, राज्य के 26 जिलों में घूमने के बाद वह 8 सितंबर 2023 को तिरुपति पहुंची जहां उसके समापन पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। बस प्रचार यात्रा ''राज्य को बचाओ और देश की रक्षा करो'' के नारे के साथ शुरू हुई थी। तिरुपति में बस यात्रा के समापन कार्यक्रम के सिलसिले में एक शानदार जुलूस के बाद आम सभा की गई।

आम सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कहा कि लाल झंडे से ही देश की रक्षा की जा सकती है और देश के लिए एक बेहतर भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है। उन्होंने आह्वान किया कि देश की जनता को आगामी 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आजादी पाने के लिए संघर्ष किया था और आज भाजपा की नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार, जो जनविरोधी नीतियां अपना रही है, उसके खिलाफ भी आज कम्युनिस्टों को जुझारू संघर्ष करना होगा। यह सरकार क्षेत्रवाद, धर्म और जाति जैसे मुद्दे उछालकर देश की जनता का सांप्रदायिक लाइनों पर ध्रुवीकरण करने के आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है और अपने राजनीतिक फायदों के लिए ''फूट डालो और राज करो'' के सिद्धांत पर चल रही है। अपने पिछले 9 सालों के कार्यकाल में इस सरकार ने देश के विकास का कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया परंतु इस समय शेखी बघार रही है कि देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी। इसके इस तरह के दावे मिथ्या और तर्कहीन हैं। एक तरफ बेरोजगारी खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है और दूसरी तरफ मोदी देश के लोगों को बहका रहे हैं कि भारत चमक रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। 2019 के चुनावों से पहले उन्होंने दो करोड़ नए रोजगार प्रति वर्ष सृजन करने का वायदा किया था। इसके अनुसार पिछले 9 सालों में 18 करोड़ नए रोजगार पैदा हो जाने चाहिए थे। परंतु हकीकत यह है कि नए रोजगार पैदा होना तो दूर रहा बड़ी संख्या में मौजूदा रोजगार भी खत्म हो गया है और बड़ी संख्या में मजदूरों और कर्मचारियों से रोजगार छिन गया है। मोदी को जवाब देना होगा कि 9 साल की अवधि में उन्होंने कितना रोजगार पैदा किया है। उन्होंने विदेशी बैंकों में भारत के लोगों द्वारा जमा किए गए काले धन को वापस लाकर हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वायदा भी किया था। अब बताएं कितने लोगों के खाते में यह पैसा जमा कराया गया? उन्हें जवाब देना होगा कि देश के विकास की दिशा में उन्होंने वास्तविक तौर पर क्या किया है?

डी. राजा ने आगे कहा कि मोदी के शासन में आम जनता को कुछ नहीं मिला है परंतु अंबानी और अडानी को भारी फायदे पहुंचे हैं। मोदी का मुख्य लक्ष्य जनता को धोखा देना रहता है। वह आरएसएस के एजेंडे पर अमल करते हैं और संसद के प्रति उनकी कोई सम्मान की भावना ही नहीं। अब आरएसएस के निर्देश पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। परंतु उसका एजेंडा ही नहीं बताया। इससे समझा जा सकता है कि वह संसद और

शेष पेज 14 पर

सच्चाई की कसौटी पर जी–20

संपादकीय

जी–20 शिखर सम्मेलन के इर्द–गिर्द मोदी सरकार ने जो सालभर का महोत्सव चलाया था वह समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी महत्वाकांक्षाओं के कारण इसकी रचना इसके सामाजिक–राजनीतिक और कूटनीतिक विषय वस्तु की जगह उत्सव के रूप में अधिक की थी।

चूंकि जी–20 की अपनी प्रकृति और घोषित उद्देश्यों से उम्मीद थी कि यह विश्व के सम्मुख मौजूदा सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि इस तरह के मुद्दों पर बीच–बीच में नाममात्र के इशारे होते थे, नरेन्द्र मोदी का जोर 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की वास्तविकता से बड़ी छवि तैयार करने में था। इस उद्देश्य के लिए जी–20 की अध्यक्षता बड़ी चालाकी से इस्तेमाल की गई। यह आमतौर पर जाना जाता है कि जी–20 अध्यक्षता इसके सदस्य राष्ट्रों को बारी–बारी से मिलती है, लेकिन मोदी और इसके स्ट्रोमट्रूपर्स ने एक ऐसी छाप रचने की कोशिश की कि यह मोदी की विश्वगुरु छवि के कारण दूसरे सदस्य देशों ने उस पर यह जिम्मेदारी सौंपी है।

जी–20 शिखर सम्मेलन की योजना इस तरह की बनाई गई थी कि इससे पहले 100 कार्यक्रम देश के लगभग सभी बड़े शहरों में आयोजित किए गए थे। इस व्यापक पैमाने पर लामबंदी कसरत का नतीजा पूर्ण रूप से लोगों को पता नहीं है, लेकिन संबंधित स्रोतों ने अनुमानतः बताया है कि इस महान आयोजन के मात्र संचालन में 4100 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुनः अपनी अनुरक्ति आकर्षक नारों और रंगीन अभियानों के प्रति सिद्ध की। इस शिखर सम्मेलन का नारा ''एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य''।

बेशक असावधान दर्शक के लिए इन शब्दों की सतही अपील हो सकती है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन का राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक परिणाम इस नारे के प्रति खरा नहीं था। जी–20 के विकास पथ का जी–7 की मूल स्थापना से विश्लेषण करना रोचकपूर्ण है। जी–7 की पहल 1975 में तेल संकट के तुरंत बाद की गई थी। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिरता पर पड़े संकट के नुकसान को अपने तरीके से कम करने के रास्ते खोज रही थी। जब भू–राजनीतिक घटनाओं ने विकासशील देशों की आकांक्षाओं को अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के सामने रखा तब यह जरूरी था कि जी–7 को बढ़ाकर जी–20 बनाया जाए। जी–20 का जन्म एकमत पहल नहीं थी, लेकिन यह मजबूरियों के उफान के कारण हुआ था। जी–20 में प्रत्येक मुद्दे पर की गई चर्चा में मुट्ठीभर विकसित देशों और कई विकासशील देशों के हितों के बीच टकराव हुए थे। दिल्ली शिखर सम्मेलन इसका कोई अपवाद नहीं था।

इस शिखर सम्मेलन की चर्चाओं और दिल्ली घोषणा पर सावधान नजर स्वयं जी–20 के, जो कि कथित रूप से राष्ट्रों का एक अधिक समावेशी समूह है, चरित्र पर जी–7 की अपनी परछाई को अंकित करने की कोशिश के दबावों को उद्घाटित करती है। जहां जी–20 का प्राथमिक रूप से वैश्विक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर लक्ष्य है वहीं इस शिखर सम्मेलन की बहसों के केंद्र में इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं था। यूक्रेन युद्ध एक ज्वलंत विषय था चूंकि कूटनीतिज्ञों ने बहस की थी कि किस तरह से इस मुद्दे को जी–20 नेताओं की घोषणा में शामिल किया जाए। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रवासन जैसे गंभीर समझौतों पर चर्चाओं में और मीडिया दोनों की में नाममात्र का ध्यान दिया गया था। भारतीय लोग अभी भी यह समझने की कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से जी–20 शिखर सम्मेलन भारत के लोगों की आजीविका पर प्रभाव डालेगा जैसा कि हमारे देश में भाजपा शासन के अन्तर्गत चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों के लिए वन और प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित कानूनी लूट अबाधित रूप से जारी है। प्रधानमंत्री भी बायोफ्यूल एलायन्स नाम की एक अन्य अपनी प्रिय योजना का प्रचार चाहते हैं। मोदी के विशाल चीजों के वादों के रिकॉर्ड और उन वादों की पूर्ति में असफलताओं को देखते हुए बायोफ्यूल एलायन्स के रूप और क्रियान्वयन को देखना अभी बाकी है। सोलर एलाएन्स नाम की उनकी एक और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू नहीं हो सकी।

अस्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव मोदी के शासन की विशिष्टताएं हैं। इस अन्तरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भी जवाबदेही का पूर्ण अभाव है जिसके लिए भारतीय करदाताओं ने धन अदा किया। जहां प्रधानमंत्री दुनिया भर के नेताओं के साथ तनकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे, उनमें से कोई भी खुलकर पत्रकारों के साथ बात नहीं कर पाया। खबरें उठी थी कि परम्परा के अनुसार, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पत्रकारों के साथ बातचीत करना चाहते है, लेकिन इस प्रस्ताव को नकार दिया गया था। बाइडेन को अगले दिन सुबह वियतनाम से प्रेस को संबोधित करना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में मोदी सभी से दूर रहना चाहते थे। बाइडेन ने कहा कि ''जैसाकि हमेशा करता हूं, मैंने श्रीमान मोदी के सथ मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण के लिए मानव अधिकारों के सम्मान और नागरिक समाज और मुक्त प्रेस के महत्व को उठाया था'', हम अमरीका के मानव अधिकारों के बहुत ही खराब रिकॉर्ड को जानते हैं। इसके बावजूद, अभी हाल में मणिपुर में मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों, चुनिंदा नागरिक समाज समूहों को निशाना बनाने और प्रेस में आलोचना पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध की रोशनी में ये चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। तिस पर भी, मोदी और उसके चाटुकार आक्रामक रूप से 'विश्वगुरु' की कहानी फैला रहे हैं, इस बात को छिपाकर कि कैसे दूसरे इस 'विश्वगुरु' को देखते हैं।

जी–20 नेताओं की नई दिल्ली घोषणा पश्चिमी दुनिया और रूस और चीन के नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने और तुष्ट करने की कोशिश रही है। इसमें दुनिया को बचाने के सभी तरह के आम नुस्खे हैं, जिसमें इस समूह के भीतर के गहरे प्रतिद्वन्द्वों और फटन पर नाममात्र की बात हुई। फिर भी घोषणा का एक अंश ध्यान आकर्षित करता है। घोषणा का पैरा 78 सभी हिस्सेदारों से ''धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता बढ़ाने'' के लिए अनुरोध करता है। भारत में लोगों की इन शब्दों पर हाल की यादें हैं और कैसे आरएसएस–भाजपा नेतृत्व, जो कि प्रधानमंत्री को नियंत्रित करता है, ने लगातार विविधता, संवाद और सहिष्णुता को बुरे के रूप में प्रचारित किया है। 'विश्व गुरु' की मेजबानी में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन के ये शब्द परीक्षा सूचक हैं जिनपर मोदी एवं कम्पनी का साबित करना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी एक है। हम सभी जानते हैं कि किसने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा और कहा कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। मोदी सरकार ने चुस्ती के साथ सरकार के आलोचकों पर दंडात्मक कार्यवाही द्वारा संसद में भी सभी तरह की बातचीत बंद कर दी है। मोदी को लगातार सत्ता में रहने से समाज में व्यवस्थित रूप से असहिष्णुता पैदा की गई है। मोदी के अतिकाय 'विश्वगुरु' वर्णन को व्यवहारिक कामों से मापा जाना चाहिए। इस मामले में 56 इंच छाती बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगी।

राजस्थान किसान सभा ने किये अहम फैसले

तारा सिंह सिद्धू

जयपुरः राजस्थान किसान सभा ने अपनी राज्य परिषद की विस्तृत मीटिंग में राज्य के किसानों की मांगों, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अहम प्रस्ताव पारित किए और भावी आंदोलन के कार्यक्रम तय किए। किसान सभा की मीटिंग की अध्यक्षता साथी ईशरा राम बिश्नोई ने की।

इस मीटिंग में अखिल भारतीय किसान सभा की राष्ट्रीय सचिव पश्य पद्मा, तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सुखदेव सिंह जम्मू उपस्थित रहे। जिन्होंने किसान सभा की राष्ट्रीय परिषद के निर्णयों की रिपोर्टिंग की और आवश्यक मार्गदर्शन किया। साथी तारा सिंह सिद्धू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसपर साथियों ने खुलकर अपने विचार रखे। राज्य परिषद ने अपनी मीटिंग में संगठन संबंधी निर्णय लिये। राज्य परिषद ने स्पष्ट किया कि बेशक ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाब में केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानून वापस ले लिए और एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर उन्हें पूरा करने का लिखित आश्वासन भी दिया परन्तु इस दिशा में केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया उल्टे खेती किसानी पर हमले जारी हैं। बिजली विधेयक 2022 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सहकारिता जो पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है उस पर कानून बना दिया गया है। गेहूं, चावल के निर्यात पर रोक, प्याज के निर्यात पर 24 प्रतिशत निर्यात शुल्क, आयात निर्यात की किसान विरोधी नीति यहां तक कि नीति आयोग का महंगाई के लिए एमएसपी को दोषी ठहराया जाना सब केंद्र सरकार के खेती किसानी को कारपोरेट हाथों में सौंपने के कदम हैं। किसानों की कर्ज माफी पर केंद्र सरकार की चुप्पी और बड़े पूंजीपतियों की चौदह लाख करोड़ की कर्ज माफी, दोषपूर्ण फसल बीमा योजना, स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग प्रमुख केंद्रीय बिंदु हैं। जिन पर अखिल भारतीय किसान सभा और देश के किसान अपने अपने तौर पर व संयुक्त तौर पर लड़ रहे हैं। केंद्र की खेती किसानी को लेकर नीतियों को संयुक्त किसान आंदोलन से ही परास्त किया जा सकता है उसमें अपनी कारगर भूमिका निभाने के लिए सक्रिय एवं मजबूत किसान सभा की जरूरत है। इसके लिए संगठन से जुड़े निर्णय लिए गए। मीटिंग में 24 अगस्त के संयुक्त किसान मजदूर दिल्ली सम्मेलन के आव्हान पर तीन अक्टूबर के लखीमपुर खीरी कांड पर, तथा 10 अक्टूबर को केंद्र सरकार के सहकारिता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

राज्य परिषद ने राज्य में उत्पन्न अकाल की स्थिति पर राज्य सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग को लेकर 15 सितंबर से 22 सितंबर तक धरने प्रदर्शन के जरिए मांगपत्र देने का निर्णय लिया। मांगपत्र में फसलों की गिरदवरी कराने, अकाल राहत के प्रबंध करने की मांग की जाएगी इसी के साथ राज्य में गुलाबी सुंडी से बर्बाद कपास की फसलों की गिरदावरी करने, नुकसान का मुआवजा देने तथा बी टी कॉटन बीज कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है जिन्होंने अपना बीज किसानों को यह कहकर बेचा था कि इसमें गुलाबी सुंडी नही लगेगी।

राजस्थान किसान सभा ने आदिवासी बहुल इलाकों में गेम सेंक्चुरी (खेल अभ्यारण्य) की स्वीकृति प्रदान करने की केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे हजारों लोगों के विस्थापन का खतरा पैदा हो गया है। किसान सभा उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए लड़ेगी।

एक अन्य प्रस्ताव में राज्य को नदी जल बंटवारे का पूरा पानी मिलने, ओट्टू हेड हरियाणा में राजस्थान की हिस्सेदारी तय करने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई है। किसान सभा ने पशु बीमा के दायरे में सभी पशुओं को लाने बीमा क्लेम को राशि दूधारू गाय, भैंस की चालीस हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने की मांग की। किसान सभा ने समुद्री तूफान के बाद जालोर, सांचौर बाड़मेर क्षेत्रों में भारी नुकसान का मुआवजा किसानों को देने की मांग सरकार से की इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि क्षेत्र में बिजली घंटे दिन में देने, कृषि कुओं के बिजली कनेक्शन देने की मांग राज्य सरकार से की गई।

राजस्थान किसान सभा ने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में अहम फैसले लिए। रिक्त पदों एवं राज्य परिषद के रिक्त पदों को भरा गया।

राज्य कार्यकारिणी का पुनः गठन कर 25 सदस्यीय समिति बनाई गई। तथा 57 सदस्यीय राज्य परिषद् रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद बनाई गई। नए पदाधिकारी जिनमें तारा सिंह सिद्धू अध्यक्ष, सूरजभान सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, इश्राराम, उम्मेद अली, कमलेश सैनी तथा नरेंद्र आचार्य सभी उपाध्यक्ष, साथी कैलाश गहलोत महासचिव, पंडित जीवराज, तथा निशा सिद्धू सचिव होंगे।

राजस्थान किसान सभा किसान सभा की सदस्यता अभियान 31 अक्टूबर तक चलाने। 50 हजार की सदस्यता भर्ती का लक्ष्य पूरा करने तथा जनवरी माह अंत तक सभी स्थानीय एवं जिला सम्मेलन पूरे करने का निर्णय लिया गया। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में राज्य परिषद की मीटिंग कर प्रगति की समीक्षा व राज्य सम्मेलन की तारीख एवं स्थान तय किए जाएंगे।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

आर. एस. यादव

रोजगार सृजन का फर्जी दावा

मोदी सरकार का विभिन्न विभागों और संस्थाओं पर दबाव है कि ऐसे आंकड़े पेश करें जिनसे दावा किया जा सके कि इस सरकार के कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। इसी तरह का एक आंकड़ा पेश करते हुए 12 सितंबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान 5.2 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए हैं। इनमें शुद्ध रूप से 2.7 करोड़ रोजगार सृजित हुए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के आंकड़ों से विश्लेषण के आधार पर एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान 4.86 करोड़ अंशधारक कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन से जुड़े। इसमें नई नौकरियों के साथ एक जगह से इस्तीफा देने के बाद दूसरी जगह नौकरी प्राप्त करने वाले शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, दोबारा नौकरी हासिल करने वाले या फिर से ईपीएफओ के अंशधारक बनने वालों को अलग कर पहली नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या शुद्ध रूप से 2.27 करोड़ रही।

एनपीएस के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 में 8.23 लाख नए अंशधारक नई पेंशन योजना से जुड़े। इसमें राज्य सरकार के अंतर्गत 4.64 लाख, गैर सरकारी क्षेत्रों में 2.13 लाख और केंद्र सरकार में 1.29 लाख अंशधारक जुड़े। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार साल में एनपीएस से करीब 31 लाख नए अंशधारक जुड़े। इसका मतलब है कि संचयी रूप से ईपीएफओ और एनपीएस में 5.2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए है।

यह शर्मनाक बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े एसबीआई रिसर्च द्वारा इस तरह के फर्जी आंकड़े पेश किए जाएं।

ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या बढ़ने का यह अर्थ निकालना सर्वथा गलत है कि नए रोजगार का सृजन हुआ है।

रिपोर्ट में पहले कहा गया है कि इस अवधि में 5.2 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए। परंतु आगे चलकर स्वयं इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने वाले लोगों की बड़ी संख्या को निकालकर देखे तो शुद्ध रूप से 2.7 करोड़ रोजगार सृजित हुए। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट का पहला कथन कि ''5.2 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए'' गलत है। इससे पता चलता है कि अनेक मजदूर ऐसे होते हैं जो एक स्थान पर काम छिन जाने के बाद कहीं दूसरी जगह काम तलाश करते हैं; वहां से भी काम छिन जाता है तो फिर अन्य किसी तीसरी जगह काम की तलाश करते हैं। इस तरह इन अस्थायी मजदूरों का एक कार्यस्थल से काम छिनने पर दूसरे किसी कार्यस्थल पर काम पाने का सिलसिला उनके जीवन भर चलता रहता है। यदि किसी मजदूर ने इस तरह पांच अलग–अलग जगहों पर काम किया है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसका नाम अलग–अलग कार्यस्थल से ईपीएफओ में दर्ज हो सकता है। अतः ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या में वृद्धि को नए रोजगार के सृजन के रूप में समझना गलत है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना तत्वतः एक किस्म की बचत स्कीम है। इस स्कीम के जरिये लोग अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ पेंशन का बंदोबस्त करते हैं। इसके अंशधारकों की संख्या में वृद्धि होने का यह मतलब कतई नहीं है कि नए रोजगार का सृजन हुआ है। जो आदमी पहले ही और वर्षों से कहीं काम कर रहा है और अब राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल हो जाए तो क्या उसे नए रोजगार का सृजन माना जा सकता है।

जाहिर है एसबीआई रिसर्च ने चार वित्त वर्षों में 5.2 करोड़ नए रोजगार सृजित होने का जो दावा किया है वह सरासर फर्जी है। समझा जा सकता है कि इस तरह की गलत रिपोर्टें और फर्जी जानकारी सरकार के दबाव में तैयार की जाती हैं। इससे इन संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो रही है।

सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनोमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार, 2016–17 में देश की कुल वर्कफोर्स 41.27 करोड़ थी जो 2022–23 में घटकर 40.5 करोड़ रह गई। अर्थात इस अवधि में 77 लाख रोजगार घट गए।

कहां तो एसबीआई रिसर्च के अनुसार, 2019–20 से 2022–23 के दौरान लगभग 5.2 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए, और कहां सीएमआई द्वारा 2016–17 से 2022–23 की सात साल की अवधि में 77 लाख रोजगार घटने की रिपोर्ट?

अडाणी हिंडनबर्ग मामले में सेबी भी गुनाहगार?

जनवरी में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अभी सितंबर में आई वैश्विक नेटवर्क ओसीसीआरपी (आर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) की रिपोर्ट ने अडाणी कारपोरेट समूह पर टैक्स हेवन देशों में अपनी फर्जी कंपनियों के जरिये शेयरों की हेराफेरी करने और गुपचुप तरीके से अपनी ही कंपनियों के शेयरों में निवेश, बही खातों में धोखाधड़ी तथा शेयरों के भाव में गड़बड़ी के साथ विदेशी इकाइयों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया है। ओसीसीआरपी ने यह खुलासा भी किया है कि डीआरआई (डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस) और सेबी के बीच एक पत्र व्यवहार हुआ था जिसमें डीआरआई ने कारपोरेट समूह द्वारा की जा रही अनियमितताओं का उल्लेख किया था और उस संबंध में कुछ सबूत भी दिए थे और सेबी से आग्रह किया था कि इस संबंध में जांच की जाए। डीआरआई का पत्र मिलने के बाद सेबी ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय अडानी समूह के खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया।

मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके संबंध में एक समिति भी नियुक्त की जिसमें अडाणी समूह और सेबी से पूछताछ भी की। परंतु सेबी ने सुप्रीम कोर्ट या समिति को कभी नहीं बताया कि उसे कभी डीआरआई से ऐसा पत्र आया या उसने पत्र मिलने के बाद जांच बंद कर दी थी। इससे प्रतीत होता है कि सेबी सुप्रीम कोर्ट से भी तथ्यों को छुपा रहा था।

अडाणी हिंडनबर्ग विवाद में जनहित याचिका दायर करने वालों में से एक अनामिका जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया और अडाणी की कंपनियों की ओर से कथित स्टाक हेरफेर पर डीआरआई के पत्र को नजरअंदाज किया। सेबी ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था उसने अडाणी समूह के खिलाफ दो आरोपों को छोड़कर सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली है और अडाणी समूह में निवेश करने वाली विदेशी इकाइयों के वास्तविक मालिकों के बारे में पांच टैक्स हेवन देशों से अब भी सूचना का इंतजार है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सेबी का व्यवहार इस तरह का रहा है मानो वह अडाणी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले में लीपापोती करने और अडाणी समूह को क्लीनचिट देने की कोशिश कर रहा है। परंतु ओसीसीआरपी की रिपोर्ट से नजर आने लगा है कि अडाणी समूह को क्लीनचिट देने की कोशिश स्वयं सेबी को ही इस मामले में एक गुनाहगार बना सकती है।

द इंडियन एक्सप्रेस (4 सितंबर 2023) कहता है कि ''सेबी को जवाब देना होगा''। पत्र लिखता है: हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट को देखते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस प्रकरण में उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर करना शुरू दिया, जिसमें उनके खिलाफ आरोप और समूह एवं स्टॉक की कीमतों में संभावित हेरफेर भी शामिल हैं। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में मोटे तौर पर सेबी की जांच के दायरे और सीमा को रेखांकित किया गया जबकि समिति ने निष्कर्ष निकाला कि नियामक विफलता का कोई सबूत नहीं है, पिछले सप्ताह की कई रिपोर्टें, जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता और शेयर बाजार गतिविधि जैसे मुद्दों पर विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं, अन्यथा सुझाव देती हैं। ये रिपोर्ट नियामक तंत्र में कमियों की ओर इशारा करती हैं, और ऐसे सवाल उठाती हैं जिस पर शेयर बाजार नियामक को तत्काल ध्यान देने की जरूरत हैं।

पिछले मंगलवार को, इस अखबार की एक रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच का विवरण दिया गया था, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि टैक्स हेवन देशों में स्थित विदेशी निवेशकों सहित एक दर्जन कंपनियां, अडाणी समूह की कंपनियों की कम बिक्री से ''शीर्ष लाभार्थी'' थी। वास्तव में, इनमें से कुछ निवेशकों ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने से कुछ दिन पहले ही पोजीशन ले ली थी। हालांकि, इनमें से किसी भी इकाई ने आयकर अधिकारियों को स्तरीय स्वामित्व संरचनाओं का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने अपने निष्कर्षों को सेबी के साथ साझा किया था। उसके कुछ दिनों बाद, एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे दो व्यक्ति–एक संयुक्त अरब अमीरात से और दूसरा ताइवान से–जिन्होंने अडाणी समूह की कंपनियों में बड़े पद ले रखे थे, विनोद अडाणी (गौतम अडाणी के भाई) के सहयोगी थे। यदि इन व्यक्तियों को विनोद अडाणी के प्रॉक्सी के रूप में माना जाता था और प्रमोटर समूह के हिस्से के रूप में माना जाता था, तो इसका मतलब यह होगा कि अडाणी समूह की कंपनियों ने शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन किया होगा। इस पेपर की एक अन्य रिपोर्ट से पता चला है कि ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत दो ऑफशोर शेल कंपनियां जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अडाणी समूह के शेयरों में निवेश किया है, वे भी समूह से जुड़ी हुई हैं। अडाणी समूह द्वारा जारी किए गए खंडन ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं किया है।

सेबी के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं, और यह सही भी है। यदि नियामक की ''विधायी नीति'' उसकी ''जांच और प्रवर्तन'' की विपरीत दिशा में चलती है, तो यह इसके परिचालन स्पेस को सीमित कर देती है, और इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को कम कर देती है।

आशंकाएं तब भी बढ़ जाती हैं जब एक पूर्व सेबी अध्यक्ष, जिनके कार्यालय का रिपोर्ट में लगाए गए कुछ आरोपों से संबंध है, अडाणी समूह के स्वामित्व वाले एक नए चैनल के स्वतंत्र निदेशक और गैर–कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। शेयर बाजार नियामक के रूप में सेबी का प्राथमिक कर्तव्य बाजारों की अखंडता सुनिश्चित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। अच्छा होगा कि सेबी उठाए गए सवालों का व्यापक तरीके से समाधान करने के लिए काम करे।

महंगाई की मार

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने 5 अगस्त को खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जिसके अनुसार, अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 6.8 प्रतिशत पर आ गई जो जुलाई में 7.4 प्रतिशत थी। खुदरा मुद्रास्फीति औसत उपभोक्ता द्वारा अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति दर है (या वह दर है जिस पर सामान्य कीमतें बढ़ती हैं)। आम तौर पर इसका कैलकुलेशन साल–दर–साल आधार पर किया जाता है। अगस्त 2023 में 6.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अर्थ है कि उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाला सामान्य मूल्य स्तर (खाद्य कीमतों, सेवाओं की कीमतों आदि का समग्र) अगस्त 2023 में अगस्त 2022 की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक था।

भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के लिए 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर को आदर्श मानता है और इसे अपना लक्ष्य मानता है। इस प्रकार अगस्त 2023 की 6.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर रिजर्व बैंक की 4 प्रतिशत की लक्ष्य दर से अधिक है। भारत जैसे देश के लिए जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुजारे लायक कमाई के लिए संघर्ष करता है वहां 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर भी आम आदमी के लिए असहनीय है। आम आदमी की आमदनी का बड़ा हिस्सा खाद्य सामग्रियों पर खर्च होता है और अगस्त में खाद्य कीमतों में मुद्रास्फीति दर 9.9 प्रतिशत थी।

शेष पेज 15 पर...

खाद्य आंदोलन के शहीदों की याद में आयोजन

सुबोध दत्ता

कोलकत्ता: भारी बारिश और आपदा को नजरअंदाज करते हुए, 31 अगस्त 1959 के खाद्य आंदोलन के शहीदों की याद में वाममोर्चा द्वारा एस्प्लेनेड में 31 अगस्त को आयोजित सभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दिन उमड़े हुजूम और जनसैलाब ने यह साबित कर दिया कि भले ही राज्य की विधानसभा और लोकसभा में वाममोर्चा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन राज्य से वाममोर्चा और लाल झंडे का नामोनिशान मिट नहीं गया। वाममोर्चा जनता के पक्ष में सड़क पर आंदोलन कर रहा है। रैली में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और रोजगार की मांग के खिलाफ राज्य में सांप्रदायिक फासीवादी भाजपा और भ्रष्ट तृणमूल सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम का समय दो बजे निर्धारित था। लेकिन उससे काफी पहले ही हावड़ा और सियालदह से जुलूस आने शुरू हो गये थे। बूंदाबांदी को नजरअंदाज कर लोग जवाहर लाल नेहरू रोड पर उमड़ पड़े। हालांकि बारिश से भीड़ अस्थायी रूप से तितर–बितर हो जाती है, लेकिन बारिश कम होते ही लोग फिर से इकट्ठा होने ल ग ` । छात्र–युवा–महिलाएं–मजदूर–किसान–खेत मजदूर बारिश को नजरअंदाज कर वामपंथी नेताओं के भाषण सुनने के लिए नारे लगाने लगाते हुए शामिल हुए।

सभी ने जन आंदोलन में मारे गए लोगों और राज्य में पिछले पंचायत चुनाव में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर अपने काम की शुरुआत की।

बैठक की अध्यक्षता वाममोर्चा के चेयरमैन बिमान बसु ने की। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 1959 को गांव के मजदूर–किसान–खेत–मजदूर भोजन की मांग को लेकर शहीद मीनार की तलहटी में आकर एकत्र हुए। जुलूस राजभवन की ओर बढ़ा। शांतिपूर्ण मार्च

पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार के मुताबिक पुलिस लाठीचार्ज में 80 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। दरअसल, ज्यादा लोग मरे थे। आज फिर देश में खाने–पीने की चीजों और ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र की सांप्रदायिक भाजपा सरकार और राज्य की भ्रष्ट तृणमूल सरकार कीमतों को नियंत्रित करने और रोजगार पैदा करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। साम्प्रदायिकता और मनमानी के खिलाफ लड़ाई तेज करनी होगी। उन्होंने एक मांगपत्र भी दिया।

मांगों के समर्थन में भाकपा के राज्य सचिव स्वप्न बनर्जी ने कहा कि बारिश की परवाह न करते हुए यह विशाल रैली केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आगाह करना चाहती है कि जनता जाग चुकी है, सावधान रहें, आपके दिन खत्म होने वाले हैं। भोजन सहित दैनिक अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, रोजगार का कोई अवसर नहीं है। लोग बेरोजगार हैं। केंद्र की सांप्रदायिक भाजपा सरकार देश को टुकड़े–टुकड़े कर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और राज्य की भ्रष्ट तृणमूल सरकार नौकरियां बेचने और कोयला, मवेशी और रेत की तस्करी में व्यस्त है। कुछ नेता और मंत्री आज जेल में हैं। इन दोनों सरकारों को हटाकर केंद्र और राज्य में जनता की सरकारें स्थापित की जानी चाहिए।

सीपीआई (एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि इस राज्य में खाद्य आंदोलन चल रहा है। हम देश को कॉरपोरेट के हाथों में नहीं जाने देंगे, हम राज्य को लुटेरों के हाथों से बचायेंगे।

फारवर्ड ब्लॉक के नरेन चटर्जी, आरएसपी के तपन होर और अन्यों ने भी सभा को संबोधित किया।

मीटिंग में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे भाकपा से प्रबीर देब, तपन गांगुली, कल्याण बनर्जी, गौतम रॉय, सीपीआई (एम) से सूर्यकांत मिश्रा, रामचन्द्र डोम इसके अलावा अन्य वाम दलों के लोग भी शामिल थे।

इस दिन सुबह के समय वाम दल के नेताओं ने राजा सुबोध मलिक स्क्वायर पर शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की और माल्यार्पण किया।

भाकपा का केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 11 सितंबर से प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन

पटना, 9 सितंबर 2023। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और सभी भूमिहीनों को पांच डिसमल वासरहित आवासीय जमीन देने की मांग को लेकर 11,12 और 13 सितंबर को बिहार के सभी प्रखंड सह अंचल पर धरना प्रदर्शन करेगी।

पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा महंगाई, बेरोजगारी और बिहार को सुखाग्रस्त राज्य घोषित करने, भूमिहीनों को पांच डिसमल वासरहित आवासीय जमीन देने की मांग को लेकर राज्य के सभी प्रखण्ड मुख्यालयों पर धरना–प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी पूरे राज्य में जोर शोर से चल रही है। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना किसी को नहीं उजाड़ा जाये। सरकार सभी भूमिहीनों को वास के लिए पांच डिसिमिल जमीन दे। जहाँ सरकारी जमीन नहीं है वहाँ खरीद कर दे। सरकार छह लेन सड़क निर्माण के लिए ऊंची कीमत पर जमीन खरीद सकती है तो भूमिहीनों के लिए क्यों नहीं? उन्होंने बिहार सरकार से भूमि सुधार के लिए गठित डी बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि मोदी सरकार के नौ वर्षो के कार्यकाल में महंगाइ आसमान छू रही है। खाद्य वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दाल, चावल, आटा, हरी सब्जी, प्याज, मशाले की कीमत लगातार बढ़ रही है। भोजन की थाली 65 फीसदी महंगी हो गई है। महंगाई के कारण गरीबों को दो जून की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महंगाई पर रोक लगाने और सभी भूमिहीनों को पांच डिसमल वासरहित आवासीय भूमि देने की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर धरना–प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। भाकपा राज्य सचिव ने बिहार के आम अवाम से प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।

महंगाई के चलते 47 फीसदी लोगों ने जीवन बीमा पॉलिसी लौटा दी

पटना, 13 सितंबर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार की जनविरोधी आर्थिक नीति के चलते एक आम परिवार का घर चलाना मुश्किल हो गया है। जानलेवा महँगाई का परिणाम यह है कि जरूरी जीवन बीमा पॉलिसी भी लोग सरेंडर करने पर मजबूर हो गये हैं। पिछले 5 सालों में 47 फीसदी लोगों ने जीवन बीमा पॉलिसी लौटा दी है।

भाकपा राज्य सचिव ने बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षो के कार्यकाल में महंगाई आसमान छूने लगी है। इसका असर लोगों के जीवन यापन पर पड़ने लगा है। लोग अपनी भोजन जैसी महत्वपूर्ण आवश्यक आवस्यकताओं के सामानों में कटौती कर जीवन बीमा का पॉलिसी कराते हैं, लेकिन मोदी सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण जीवन बीमा कराने वाले 47 फीसदी लोगों ने अपनी किस्त जमा करना बंद कर दिया है या पॉलिसी लौटा दी है। मोदी सरकार में पूंजीपतियों की संपत्ति दिन दूनी रात चौगूनी बढ़ रही है वहीं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य वस्तुओं के साथ साथ मसालों की कीमत में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। भोजन की थाली 65 फीसदी महंगी हो गई है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि महंगाई पर रोक लगाने के नारे के साथ केंद्र में आई मोदी सरकार महंगाई रोकने में फिसड्डी साबित हुई है। महंगाई की मार से सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग त्रस्त है। गरीबों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई रोकने में विफल मोदी सरकार को देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का कार्य करेगी।

मोदी के झूठे विकास के दावे बेनकाब

नरेंद्र मोदी सरकार का यह दावा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, अब पकडा गया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर अशोक मोदी, जो प्रधानमंत्री के उपनाम का एक होमोफोनिक संस्करण रखते हैं, का दावा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने यह गलत कहा है कि पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में भारत की जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

उक्त प्रोफेसर, जो दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने सत्तर के दशक की शुरुआत में पढ़ाई की थी, का तर्क है कि यह वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत होना चाहिए, जिसके जाहिर होने पर इस सप्ताह के अंत में शुरू होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के नेताओं के दिल्ली आने से पहले मोदी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती।

प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए लिखे गए और 'भारत की नकली विकास कहानी' शीर्षक वाले एक लेख में, मोदी 'उभरते भारत की सावधानीपूर्वक तैयार की गई छवि' पर सवाल उठाते हैं कि वह अपने नाम के लिए तैयार कहानी है। प्रोजेक्ट सिंडिकेट एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन है जो विभिन्न वैश्विक विषयों पर टिप्पणी और विश्लेषण प्रकाशित और सिंडिकेट करता है।

यह 'हेराफेरी' इसलिए तैयार हो पाती है क्योंकि एनएसओ एक समग्र आंकड़ा पेश करने के लिए और उन्हें तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रथा का पालन नहीं करता है जबकि सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए दो मानदंड काफी भिन्न संख्याएं पेश करते हैं।

एनएसओ वास्तविक जीडीपी को दो तरीकों से मापता है: पहले उत्पादन/आय दृष्टिकोण के माध्यम से और फिर व्यय दृष्टिकोण के माध्यम से।

आम तौर पर दोनों संख्याओं के बीच अंतर होता है और एनएसओ सकल घरेलू उत्पाद के अपने व्यय–आधारित अनुमान में विसंगतियों के तहत अंतर को जोड़कर दोनों को संतुलित करता है।

मोदी, जिन्होंने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक अर्थशास्त्री के रूप में लंबे समय तक काम किया है, लिखते हैं: "सिद्धांत रूप में, व्यय अर्जित आय के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उत्पादक केवल तभी आय अर्जित कर सकते हैं जब अन्य लोग उनका उत्पादन खरीदते हैं। हालाँकि, व्यवहार में, आय और व्यय के अनुमान हर जगह राष्ट्रीय खातों में भिन्न होते हैं, क्योंकि वे अपूर्ण डेटा पर आधारित होते हैं।

आम तौर पर, विकास दर की गणना के लिए यह विसंगति मायने नहीं रखती है, क्योंकि आय और व्यय, भले ही वे कुछ हद तक भिन्न हों, परंतु वे रुझान समान ही रखते हैं।

मोदी कहते हैं कि समय–समय पर, दोनों श्रृंखलाएं बहुत अलग–अलग रास्तों का अनुसरण करती हैं, जिनके आर्थिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बेहद परिणामी निहितार्थ होते हैं।

मोदी कहते हैं, लेकिन इस साल एक समस्या है, क्योंकि अप्रैल–जून में उत्पादन से आय में वार्षिक 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जबकि व्यय में मामूली 1.4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

मोदी का मानना है कि एनएसओ को दो आंकड़ों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, जबकि विकास की कहानी में काफी अंतर है।

यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार में लाये जाने वाले अभ्यास मानदण्डों का स्पष्ट उल्लंघन है। विसंगति रेखा का संपूर्ण उद्देश्य सांख्यिकीय खामियों को स्वीकार करना है, न कि उन्हें गायब करना। प्रोफेसर लिखते हैं कि एनएसओ ऐसे समय में व्यय में कमी की वास्तविकता को ढक रहा है जब कई भारतीय इससे पीड़ित हो रहे हैं, और जबकि विदेशी भारतीय वस्तुओं के लिए केवल सीमित भूख (मांग) दिखा रहे हैं।

प्रो. अशोक मोदी एक तरह से एक ट्रेंडसेटर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक की डिग्री के साथ आईआईटी मद्रास से स्नातक होने के बाद, वह तिरुवनंतपुरम में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने चले गए, जहां उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में पीएचडी पूरी करने से पहले एम फिल की उपाधि प्राप्त की।

वह कहते हैं कि उचित दृष्टिकोण आय और व्यय दोनों को अपूर्ण व्यापक आर्थिक समुच्चय के रूप में पहचानना है, और फिर इसे अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए उन्हें संयोजित करता है। इसलिए, ऑस्ट्रेलियाई, जर्मन और यूके सरकारें आय और व्यय दोनों पक्षों की जानकारी का उपयोग करके अपनी रिपोर्ट की गई जीडीपी को समायोजित करती हैं।

वो आगे लिखते हैं कि अमेरिका व्यय को अपने आर्थिक प्रदर्शन के प्राथमिक मीट्रिक (भारत में आय के विपरीत) के रूप में उपयोग करता है।

यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस दोनों के औसत को अपनी समग्र माप के रूप में रिपोर्ट करके आय और व्यय के बीच अक्सर बड़े अंतर का हिसाब लगाता है। जब हम बीईए पद्धति को भारतीय डेटा पर लागू करते हैं, तो सबसे हालिया विकास दर की हेडलाइन 7.8 प्रतिशत से गिरकर 4.5 प्रतिशत बन जाती है–अप्रैल –जून 2022 में 13.1 प्रतिशत के बाद से एक उल्लेखनीय गिरावट है। प्रोफेसर का तर्क है कि यह मौजूदा इंडिया हाइप लहर पोस्ट–कोविड–19 रिबाउंड से शुरू हुई है।

बहुत से अर्थशास्त्री मोदी के इस रेडिकल नारेबाजी जैसे तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

भारत संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 का पालन कर रहा है और तिमाही विकास डेटा के साथ समस्याएं कोई नई बात नहीं हैं और यह न ही केवल भारत के लिए विशिष्ट हैं। बेंगलुरु में डॉ. बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति एनआर भानुमूर्ति कहते हैं कि तिमाही आधार पर विकास की मात्रा निर्धारित करने के अपने जोखिम हैं।

त्रैमासिक जीडीपी कई प्रमुख संकेतकों पर आधारित है जो एक मजबूत प्रवृत्ति दिखाते हैं। हालाँकि, अनुमानों को थोड़े से नमक के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक वृद्धि दर वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर के अंतिम संशोधन के बाद देखी जा सकती है।

भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने हालिया इकोरैप रिपोर्ट में कहा कि विनिर्माण, निर्यात और सेवा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य विशिष्ठ क्षेत्रों में प्रमुख संकेतकों के संबंध में एनएसओ की डेटा पद्धति में संभावित गलतियां थीं। रिपोर्ट में इस बात पर भी आश्चर्य जताया गया कि क्या पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों की व्याख्या पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के डेटा से संकेत मिलता है कि जीडीपी और जीएनआई (आधिकारिक तौर पर 'सांख्यिकीय विसंगति' के रूप में जाना जाता है) के बीच का अंतर आम तौर पर लगभग एक प्रतिशत है। यह विसंगति अमेरिका सहित कई अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रही है।

जीडीपी एक निर्धारित समय अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। जीएनआई देश को उसके निवासियों और व्यवसायों से प्राप्त कुल आय है, चाहे वे देश में स्थित हों या विदेश में।

जीडीपी और जीएनआई में अंतर यह दर्शाता है कि देश शुद्ध प्राप्ति या शुद्ध देय है। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011–12 से 2019–20 के दौरान जीडीपी और जीएनआई के बीच औसत अंतर लगभग 1.1 प्रतिशत था। हालाँकि, यह अंतर 2020–21 में मामूली रूप से बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गया और फिर 2021–22 और 2022–23 दोनों में उल्लेखनीय रूप से दो प्रतिशत हो गया है।

प्रलेसं: जबलपुर घोषणापत्र

आज से 43 वर्ष पूर्व 1980 में इसी जबलपुर में प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल, हम समस्त भारतीय भाषाओं के लेखकों ने प्रगतिशील लेखन आंदोलन की गौरवशाली परम्परा और विरासत के प्रहरी के रूप में, स्वाधीन भारत में जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी आदर्शों की रक्षा के लिए स्वयं को संकल्पित किया था। आज जब हम फिर प्रगतिशील लेखक संघ के इस अठारहवें राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साथ हैं, तब स्वाधीनता आंदोलन द्वारा संजोये गये संविधान संरक्षित समता, समानता और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के मूल्यों को बचाने की नयी चुनौती दरपेश है।

भारतीय जनतंत्र आज अस्तित्व के जिस संकट से रुबरू है, ऐसा पहले कभी नहीं था। हम देख सकते हैं कि इस सदी में, खासकर पिछले एक दशक से तर्कशीलता, बहुलतावाद, वैज्ञानिक सोच और प्रगतिशील जीवन दृष्टि को नष्ट करते हुए अतीतोन्मुखी, प्रतिगामी, बहुसंख्यकवादी, अंधविश्वासी और पुनरुत्थानवादी विचारों को सांस्थानिक रूप से स्थापित और महिमामंडित किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र को बहुसंख्यवादी धर्मतंत्र में बदलने के संकेत स्पष्ट हैं। स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को विरूपित और नष्ट किया जा रहा है। सामाजिकी शोध संस्थाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि में ज्ञानार्जन व स्वतंत्र बौद्धिक संवाद का वातावरण प्रदूषित कर उन्हें संकीर्ण, एकल प्रभुत्ववादी सोच में ढाला जा रहा है। भारतीय समाज की बहुभाषी, बहुलतावादी व समावेशी सांस्कृतिक सम्पदा की अनदेखी कर उसे एकांगी बनाया जा रहा है। बुद्ध, बासवन्ना और कबीर की परंपरा को मिटाया जा रहा है। गाँधी, नेहरू व आम्बेडकर सरीखे राष्ट्र नायकों की छवि को संदर्भच्युत कर धूमिल किया जा रहा है।

गंभीर चिंता का विषय यह भी है कि हिंदुत्ववादी राजनीति का पूँजीवादी सांस्थानिक और निगमीय शक्तियों से

प्रगतिशील लेखक संघ के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन (जबलपुर –20,21,22 अगस्त 2023) में जारी घोषणापत्र

सीधा गठबंधन स्पष्ट है। इस 'क्रोनी पूंजीवाद' से उस नये सर्वसत्तावाद का अवतरण हो गया है जो फासीवाद का देशज रूप है, लेकिन इसका मूल उत्स और विभाजनकारी कार्यप्रणाली हिटलरकालीन नाजीवाद से प्रेरित है। लोकतांत्रिक संरचनाओं पर सीधा संकट पैदा हो चुका है। अभिव्यक्ति और प्रतिरोध की आजादी अवरुद्ध करने के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। इस दौर में कई बुद्धिजीवी, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और संस्कृतिकर्मी बंदी बनाए गए हैं। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पान्सारे, एम. एम. कल्बुर्गी और गौरी लंकेश को तो शहादत ही देनी पड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल व अन्य मानवाधिकारवादी संस्थाओं पर जाँच के नाम पर आक्रमण किए गए हैं और उन्हें विवश किया गया कि वे अपना सामाजिक कार्य बंद ही कर दें।

नब्बे के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक पूँजीवाद द्वारा संचालित आर्थिक नीतियों ने विषमता और विपन्नता की जो राह बनायी थी, वह आज निर्मम परिणति प्राप्त कर चुकी है। रोजगार व जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में देश की अस्सी करोड़ से अधिक जनता न्यूनतम जीवनयापन सुविधाओं के लिए संघर्षरत है। शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी दायित्वों से राज्य ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। मध्यवर्ग पर भी अनावश्यक और अत्याधिक करारोपण व पेंशन सुविधाओं से वंचित वर्ग परेशान हाल है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, आर्थिक असमानता की खाई और गहरी हुई है। वर्तमान पीढ़ी का भविष्य भी संकट में है। संविधान द्वारा संकल्पित कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का परित्याग कर समूचे देश को एक 'व्यावसायिक परियोजना' में तब्दील किया जा रहा है। न्यायिक व चुनाव आयोग सरीखी अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर लेकर, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। प्रिंट और

शेष पेज 12 पर...

''एक राष्ट्र, एक उर्वरक'

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य एवं संसदीय दल नेता बिनोय विश्वम ने 1 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को निम्न पत्र में ''एक राष्ट्र, एक उर्वरक' के बैनर तले प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (पीएम–बीजेपी) के संबंध में और इस उर्वरक परियोजना को उनकी फोटो के साथ ''पीएम–बेजीपी'' के ब्रांड नाम से जारी करने से जुड़ी शर्त के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा किः0

''सर्वप्रथम, सभी उर्वरकों का एक नाम करने का तर्क अस्पष्ट है। उर्वरक के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी उर्वरक कंपनियों ने काम किया है। इन सभी उर्वरकों का एक नाम करने से न केवल इन विभिन्न कंपनियों की वह पहचान और साख जो उन्होंने बनाई है खत्म होती है बल्कि इससे किसानों के बीच जो कि किसी विशिष्ट उत्पाद को विशिष्ट जरूरत के लिए लेते हैं उनके बीच भ्रम फैलेगा। इसके अलावा, उर्वरक थैलों में ''पीएम–बीजेपी'' को विशिष्टता से छापने का निर्णय अन्य चिंताएं खड़ी करती हैं नाम और लोगो (मार्का) में संक्षिप्त रूप में ''बीजेपी'', जो कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करता है, खासतौर से आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक प्रचार अभियान के रूप में इसे आसानी से गलत समझा जा सकता है।

लगता है ''पीएम–बीजेपी'' नाम का चयन राजनीतिक कारण से किया गया है। इस तरह की कोशिश सामान्य जन की सरकार की निष्पक्षता पर विश्वास को खत्म करती है और यह करदाताओं के धन को राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल करने की कोशिश है।

हमारे देश के किसान जब उर्वरकों को पसंद करते हैं उस पर स्पष्टता, विकल्प और पारदर्शिता का अधिकार रखते हैं। एक ब्रांड को थोपना, और वह भी स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्यों के साथ, न केवल किसानों के विकल्पों को खत्म करता है बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता और फलोत्पादकता के बारे में सवाल भी उठा सकता है। हमारे किसान हमारे देश का आधार हैं, और यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि उनके हित को सर्वोपरि सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में, आपसे अनुरोध करता हूं कि ''एक राष्ट्र, एक उर्वरक'' नीति पर पुनर्विचार करें और कंपनियों को उनके उपभोक्ताओं के बीच अपनी पहचान और विश्वास को बनाए रखने की अनुमति दें।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तत्काल उर्वरक थैलों से ''पीएम–बीजेपी'' मार्के को हटाए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें राजनीतिक पक्षपात की कोई बूझ नहीं है।

डेंगू के मरीजों की इलाज की समुचित व्यवस्था करें सरकार

पटना, 12 सितम्बर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने राज्य सरकार से डेंगू पीड़ितों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। पूरे बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू से दर्जनों व्यक्तियों की मौत भी हो गई है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच और मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जाए।

भाकपा राज्य सचिव ने बयान जारी कर कहा कि राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में डेंगू का बढ़ता प्रकोप चिंता का विषय है। अस्पतालों में डेंगू की जांच की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। प्राथमिक अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक डेंगू मरीजों के लिए बेड सुरक्षित किया जाए ताकि किसी मरीज को बेड मिलने में कठिनाई नहीं हो। साथ ही अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाए ताकि मरीजों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े। ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, मरीजों को आसानी से प्लेटलेट्स उपलब्ध हो सके। डेंगू की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव और लगातार फागिंग कराई जाए।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या एक हजार से अधिक पहुँच गई है। डेंगू से राज्य में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। डेंगू के अतिरिक्त सीजनल बुखार से भी बहुत लोग पीड़ित हैं। इसलिए जिलों को विशेष अलर्ट किया जाए ताकि मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। अस्पतालों में जांच के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

आईडीपीडी का मणिपुर राहत कैम्पों का दौरा

इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के एक प्रतिनिधि दल ने मणिपुर के मैतई समुदाय और कुकी समुदाय वाले क्षेत्रों का दौरा 1 से 2 सितंबर 2023 को राहत कैम्पों में उनकी स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया। आईडीपीडी ने कैम्पों की दुर्दनीय स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है।

दौरे पर निकली आईडीपीडी की इस टीम में आईडीपीडी अध्यक्ष डॉ. अरूण मित्रा, महासचिव शकील उर रहमान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. रविन्द्रनाथ और सचिव डॉ. शांति और रजनी थे। टीम ने इम्फाल जिले के खुमन लेपक स्पोर्ट्स हॉस्टल के राहत कैम्पों और पहाड़ी क्षेत्र के कांगपोकपी जिले में सपरमेइना पी.एच.सी. के अंतर्गत आईआईटी राहत कैम्पों का दौरा किया।

दौरे के दिन तक मणिपुर में 334 राहत कैम्प हैं। डॉक्टरों की यह टीम राहत कैम्पों के नोडल अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिली।

– पहाड़ी क्षेत्रों में राहत कैम्पों में गंभीर बीमार मरीजों की रेफरल व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों में विस्थापित लोगों ने बताया कि यहां के सामान्य बीमार मरीजों को चिकित्सा के लिए उन्हें 150 किमी दूर नागालैंड के कोहिमा या दीमापुर के अस्पतालों में जाना पड़ता है। कुछ अपनी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए असम जाते हैं। हिंसा से पहले उन्हें बेहतर ईलाज के लिए इम्फाल के मेडिकल कॉलेजों में रेफर किया जाता था।

अभी मणिपुर में जारी हिंसा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों से घाटी क्षेत्रों में और घाटी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में आना–जाना असंभव है।

– कांगपोकपी जिला अस्पताल में वर्तमान में न कोई ऑपरेशन थियेटर है और न ही रक्त संभारण (ब्लड बैंक) की व्यवस्था है। मणिपुर विशेषज्ञ डॉक्टरों, अन्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव का सामना कर रहा है।

चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्र के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (तीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल) इम्फाल और (एक मेडिकल अस्पताल) चूड़ाचंद्रपुर जिले में है।

– कोई विशेष टीकाकरण अभियान खासतौर से खसरे के लिए राहत कैम्पों में नहीं चलाया गया है। यूएनएचसीआर और एसपीएचईआरई के मानदंडों के अनुसार 9 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए खसरे के टीके के साथ विटामिन ए की खुराक राहत कैम्पों के लिए अनिवार्य है।

– एक राहत कैम्प के शरणार्थियों और नोडल अधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से राशन वितरण में कोई हरी पत्ते वाली सब्जी/अंडा/मांस/मछली नहीं दी गई है; हालांकि स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज संगठन और कुछ लोग कभी–कभी कुछ सब्जियां मुहैया कराते हैं।

– पहाड़ी क्षेत्र के एक राहत कैम्प के नोडल अधिकारी ने बताया कि उन्हें प्रत्येक शरणार्थी के लिए एक अंडा हर तेरहवें दिन में दिया जाता है, लेकिन हरी सब्जियां नहीं दी जाती। राहत कैम्पों में दिए जाने वाले राशन में मुख्यतः चावल, दाल, आलू और खाद्य तेल दिए जाते हैं। पिछले चार महीनों से बच्चों के आहार में हरे पत्तेवाली सब्जियों और पशु प्रोटीन के अभाव में विटामिन ए की कमी के कारण उनमें रतौंधी (आंखों की बीमारी) हो सकती है।

– जिन कैम्पों का भी टीम ने दौरा किया उनमें कैम्पों की क्षमता से ज्यादा लोग थे।

– उन कैम्पों में पेयजल की उपलब्धता, नहाने–कपड़े धोने, शौचालय के पानी की उपलब्धता की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। स्वच्छता में कई गुना सुधार की जरूरत है। मासिक रक्तस्राव की सफाई के लिए सैनेटरी नैपकिन्स की सप्लाई अपर्याप्त है।

– राहत कैम्पों में और इसके आस–पास मच्छरों को भगाने (नियंत्रण) के लिए फॉगिग की कोई व्यवस्था नहीं है।

– कैम्पों में शरणार्थियों ने बताया कि उन्हें पिछले चार महीनों से राहत कैम्पों में रहने का कारण बहुत मानसिक तनाव है और उन्हें पक्का नहीं है कि वे कब अपने घरों को लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे। कई बच्चों को दुःस्वप्न आ रहे हैं। बच्चे अपने स्कूल और दोस्तों से बिछुड़े हुए हैं जो कि उनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। उनमें पोस्ट–ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) लक्षण है।

– गैर–संक्रमणीय बीमारी वाले जैसे डायबेटिक, हाई ब्लडप्रेशर, गंभीर किडनी बीमारी वाले मरीज राहत कैम्पों में हैं। कुछ मरीजों को हेमोडायलेसिस की जरूरत है।

– आईडीपीडी केंद्र और राज्य सरकार से कैम्पों की दुर्दनीय अमानवीय स्थिति में सुधार के लिए निम्न मांगें करती हैंः

– प्राथमिक शिक्षा केंद्र से गंभीर रोगियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद मणिपुर राज्य के अंतर्गत या पड़ोसी राज्यों में उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफरल की अविलम्ब मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए।

– जिला और उपजिला स्तर पर अस्थायी ऑपरेशन थियेटर अविलंब शुरू किए जाएं। राहत कैम्पों के कलस्टर गठन के बाद इनके आसपास रक्त बैंक स्थापित किए जाएं।

– राहत कैम्पों के आस–पास सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इन्टरनेट सुविधा बहाल की जाए ताकि कैम्प में शरणाथियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, टेलीमेडिसन सेवाएं उपलब्ध हो सकें। टेलीमेडिसन सुविधा का इस्तेमाल बेसिक डॉक्टरों को गुर्दे के मरीजों के लिए पेरोटोनियल डायलेसिस की ट्रेनिंग में इस्तेमाल भी किया जा सकता है और बच्चों को सांस की दिक्कत होने पर कृत्रिम श्वसन (सांस) देने (एएमबीयू) की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, टेलिमेडिसन सेवा से नवजात शिशुओं की माताओं को स्तनपान की सलाह दी जा सकती है।

– दवा और टीके की सप्लाई की मजबूत व्यवस्था को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए और आधार स्थल पर दवाओं और टीकों की चौबीसों घंटों निगरानी रखी जानी चाहिए।

– बच्चों को तत्काल खसरे के टीके और विटामिन की खुराक दी जानी चाहिए। बेहतर पौष्टिक आहार जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, माँस और मछली कैम्प के सभी तरह के शरणाथियों को सप्लाई (वितरित) की जानी चाहिए।

– कैम्पों में और कैम्पों के आसपास मच्छरों के नियंत्रण के लिए तत्काल फॉगिग की जानी चाहिए।

– जो शरणार्थी पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं उनकी राहत कैम्पों में नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक कौन्सिलिंग की जानी चाहिए।

शिक्षक दिवस और शिक्षा जगत की चुनौतियां

प्रो. अरूण कुमार

हर साल शिक्षक दिवस आते ही शिक्षकों ओर शिक्षा की वर्तमान स्थितियों पर चर्चा –परिचर्चा प्रारंभ हो जाती है। मीडिया से लेकर सामाजिक और कमोबेश राजनीतिक क्षेत्रों में भी समीक्षा और आलोचना शुरु हो जाती है। यह स्वाभाविक भी है और जरुरी भी। क्योंकि शिक्षकों को समाज के मार्गदर्शक और निर्माता की संज्ञा दी गई है, तो इसके कुछ मायने और निहितार्थ अवश्य हैं। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार–विमर्श होना स्वाभाविक है।

किसी ने ठीक ही कहा है कि शिक्षा किसी समाज और देश के विकास का सबसे मजबूत और कारगर हथियार है। किसी देश को चहुंमुखी विकसित होना है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था के चाक–चौबंद इंतजाम को दुरूस्त करना ही होगा।

यह आम धारणा और सत्य भी है कि शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षक हैं। इसीलिए उनसे समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं भी हैं और जिम्मेदारियों की उम्मीद भी। इन्हीं उम्मीदों और अपेक्षाओं के प्रति सचेत और विवेकशील होने के कारण शिक्षकों की प्रतिष्ठा और मर्यादा आदिकाल से प्रशंसनीय और पूज्यनीय रही है।

स्वतंत्रता के बाद एक आदर्श शिक्षक, महान दार्शनिक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और हिन्दुस्तान की मजबूत शिक्षा व्यवस्था के अधिष्ठाता सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन पांच सितम्बर को 'शिक्षक दिवस' के रुप में मनाए जाने का निर्णय हुआ। शिक्षक दिवस के द्वारा शिक्षकों को मान–सम्मान और एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली और यह परंपरा चल पड़ी।

स्वतंत्रता आंदोलन की आग से निकले तपे–तपाये राजनेताओं के सामने हिन्दुस्तान की शिक्षा पद्धति की मजबूत नींव रखने और खड़ा करने की एक अहम चुनौती थी। शिक्षा व्यवस्था के केन्द्र में शिक्षकों को रखकर शिक्षा नीति बनाई गई। शिक्षकों ने इसमें महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन किया। भारत विकास की राह पर शनै –शनै कदम बढाने लगा। इसकी स्पष्ट झलक प्रो डी एस कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में मिलती है। शिक्षा को कल्याणकारी योजना और मुनाफा–व्यापार से अलग मानते हुए राष्ट्रीय सामाजिक निवेश के रुप में माना गया।

कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षकों की महत्ता को रेखांकित करते हुए लिखा कि 'भारत का भविष्य क्लास रुम में तैयार होता है'। यह महज एक वक्तव्य ही नहीं है बल्कि शिक्षक के महत्त्व को बताने वाला दर्शन भी है। बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिवेश का गहरा असर शिक्षा और शिक्षकों दोनों पर हमेशा होता रहा है। उन्नीसवीं सदी में और खासकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा आजादी के बाद करीब दो दशकों तक शिक्षा के विस्तार और विकास में सामाजिक योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की स्थापना में समाज की ऐतिहासिक भूमिका रही है। साथ ही उन नवोदित संस्थानों मे कार्यरत शिक्षकों ने भी समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना उनमें प्रबल थी। इसीलिए समाज में शिक्षक सम्मान के पात्र थे। समाज उन्हें देवदूत जैसा समझता था। वेतन और अन्य सुविधाओं की घोर किल्लत के बावजूद उनका मान–सम्मान असमानांतर था। शायद इसीलिए मेधावी और होनहार लोग शिक्षक बनना चाहते थे और बने भी। शायद यही वास्तविक कारण प्रतीत होता है कि मेरे जैसे लोगों ने दो तीन सरकारी और बैंक की नौकरी को लात मारकर शिक्षक बनना कबूल किया। मन में आदर्श विचार थे, उंची नैतिकता थी और शिक्षा के द्वारा समाज बदलने का जज्बा उफान पर था। लेकिन वह हो न सका। सामाजिक और राजनीतिक परिवेश और परिस्थितियां बदलती गई, भटकती चली गई और सारे आदर्श, नैतिकता और जज्बा काफूर होता गया।

मेरी यह पक्की समझ है कि राजनीतिक बदलाव और सरकारी नीतियां समाजिक दशा–दिशा को उसकी नींव तक प्रभावित करती हैं और उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को बदल देती हैं। समय समय पर लागू की गई शिक्षा नीतियों ने शिक्षकों की स्थितियों में बदलाव भी किये और अनेक चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षानीति ने देश में तूफान खड़ा कर दिया और निजीकरण और कम्प्यूटर के प्रयोग का रास्ता खोल दिया। इस दौर में हजारों की संख्या में निजी संस्थाओं का मकड़जाल खड़ा हुआ। बढती आबादी के लिए शिक्षा का विस्तार तो हुआ, पूंजीनिवेश भी हुए परन्तु गुणवत्ता प्रभावित होती चली गई और शिक्षा मुनाफाखोरी का जरिया बन गयी। इसने शिक्षकों की अनेक कोटियां और तरह तरह का नामकरण को जन्म दिया। 1991 की उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति शिक्षा और शिक्षकों के लिए अभिशाप बन गया।राममूर्ति कमीशन के बाद ,नालेज कमीशन और फिर अंबानी–बिरला रिपोर्ट आग में घी का काम किया। देश की आर्थिक नीति का सहचर बनकर शिक्षानीति आगे बढती गई और शिक्षकों के समक्ष लगातार चुनौतियां विकराल रुप लेती चली गई। न आर्थिक नीतियां कल्याणकारी रह गई और न ही शिक्षक उसके केन्द्र में रह गए। सारी नीतियों की नींव मुनाफे पर आधारित हो गई। हायर और फायर की नीतियों की घुसपैठ शिक्षा जगत में भी कर दी गई। सरकार की नीतियों के मकड़जाल में शिक्षक अपने वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं की लडाई में उलझते चले गए। उनके आदर्श, शिक्षा तथा छात्र के प्रति उनका समर्पण कहां गुम हो गया? आज तक ठीक ठीक पता करना मुश्किल है।

किसी भी शिक्षण संस्थान की चमक वहां की शिक्षा की गुणवत्ता होती है और वह आलोकित होता है उच्च कोटि के शिक्षकों से। परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है सरकारी तंत्र ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए शिक्षकों की अनेक कोटियां स्थापित की हैं और उसका दंश पूरा समाज और शिक्षा जगत भोग रहा है। विद्यालय में शिक्षामित्र, नियोजित, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक आदि आदि नाम दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षक, एडहॉक शिक्षक, पार्टटाइम शिक्षक, ब्लॉक ग्रांट शिक्षक, संबल योजना शिक्षक आदि। ये वैसे शिक्षक हैं जिन्हें कोई सम्मानजनक सेवा शर्त और वेतनमान नसीब नहीं है। विभिन्न संस्थानों की कोटि के आधार पर शिक्षकों की अनेक कैटेगरी हैं। उदाहरणार्थ अंगीभूत महाविद्यालय, संबद्ध अनुदानित डिग्री/इन्टर महाविद्यालय, संबद्ध अनुदानित डिग्री/इन्टर महाविद्यालय आदि आदि।

'शिक्षक दिवस पर आज की चुनौतियां'

महाविद्यालय या विद्यालय हों शिक्षक बहाली/नियुक्ति की समिति एक हो। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए जिस तरह विवि सेवा आयोग है, उसी तर्ज पर विद्यालय सेवा आयोग बने। आकर्षक सेवाशर्त और वेतनमान हो। मेधावी छात्र तभी आकर्षित होंगें। छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से आकर्षक वेतनमान और सेवाशर्त पर स्थायी नियुक्ति हो। अन्य देशों की तरह शिक्षा पर कम से कम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 प्रतिशत खर्च हो। शिक्षक की अलग अलग कोटि विलोपित हो। कोई सवाल न करे कि आप किस कोटि में हैं?

इसके साथ साथ राज्य और प्रशासन शिक्षकों को मान–सम्मान देने की तमीज सीखे और शिक्षकों के साथ नौकर या कर्मचारियों की तरह वर्ताव न करे। उनसे गैर शैक्षणिक कार्य न कराये। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्वायत्ता कायम रखकर राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप न्यूनतम हो।

तब शिक्षकों की परफॉर्मेंस और जिम्मेदारी की नियमित समीक्षा हो। तभी शिक्षा जगत आलोकित भी होगा और राष्ट्रीय विकास में सहायक भी। शिक्षकों के समक्ष अपने को प्रासंगिक और सार्थक साबित करने की महान चुनौती है। शिक्षक दिवस पर इस पर गौर किया जाना चाहिए। शिक्षकों के समक्ष अपने मान–सम्मान को फिर से स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। जो उनकी कर्त्तव्य निष्ठा और समर्पण से ही संभव है। अन्यथा शिक्षक दिवस एक औपचारिक और राजनीतिक उत्सव के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा।

परन्तु यह हो भी कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 विकराल चुनौती के साथ सामने खड़ी है। बाजार और व्यापार के हवाले संपूर्ण शिक्षा होगी। जहां शिक्षक नहीं होंगे पर 'शिक्षक दिवस' होगा। इस सुनामी को झेलना और सामना करना शिक्षकों के समक्ष सबसे बडी चुनौती होगी।

गिरधर की कलम से

आरएसएस के अल्पसंख्यक विरोधी नफरती उवाच

द्वितीय सर सँघ संचालक गोलवलकर मुसलमानों और ईसाइयों के रीति रिवाज और धर्म मिटाने के प्रति कितने कृत संकल्प थे इसका अंदाजा उनके इस कथन से स्पष्ट होता है: उन्हें वेश–विन्यास, रीति–रिवाज, भवन–निर्माण, विवाह संस्कार के आयोजन, अंत्येष्ठि संस्कार एवं इसी तरह की अन्य बातों को हिन्दू जीवन पद्धति के अनुसार मानना होगा–हम उन्हें अपने धर्म में विलीन करना चाहते हैं (बंच ऑफ थॉट्स पेज231)

एक और सँघ विचारक सीता राम गोयल का कहना है:–'जो संस्कृति हिन्दू संस्कृति–सनातन धर्म की संस्कृति की शर्तो पर चलने को तैयार नही है, उसे यहां से जाना होगा। भारत में सामाजिक संस्कृति को, मिलीजुली संस्कृति को कोई स्थान नही है। भारत भूमि पर हम विजातीय संस्कृति को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के नाम पर पनपने नही देंगे।' (ऑर्गनाइजर सँघ पत्रिका 8 जनवरी 1984) जहाँ तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न है, संघ संस्थापक इसके खिलाफ थे। संघ विचारक जिन्होंने डॉ, हेडगेवार की जीवनी लिखी कहते हैं कि 'यह साफ है कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को केंद्र में रखकर काम करते थे।–लेकिन डॉक्टर साहेब को इस बात में खतरा दिखाई दिया। दरअसल वे 'हिंदू मुस्लिम एकता' के नए नारे को पसंद नही करते थे। (शेषाद्रीः हेडगेवार दि एपोक मेकर पृष्ठ 61उ, शम्सुल इस्लाम भारत में अलगाववाद और धर्म पृष्ठ 135) नाना जी देशमुख का कहना है कि–'धर्म निरपेक्षता हिंदू समाज और गैरधर्म मुस्लिम समाज के बीच एकतरफा नही हो सकती।' (ए. बी. बर्धन मासिक कम्युनिस्ट वर्ष 27 अंक 7 अप्रैल 1995, पृष्ठ 08) गिरिलाल जैन का कथन है कि 'एक बार हमारा हिंदुत्व जागृत हो जाये तो फिर जो भी हम कहेंगे वह जो होगा उचित होगा, कल्याणकारी होगा–अगर हिंदू की मुसलमान के साथ बराबरी कराई जायेग, दोनों को समान करने की कोशिश की जायेगी तो यह देश चल नहीं सकता।' (पूर्वोक्त पूर्वोक्त पेज 08) गोलवलकर साहेब का कहना है कि 'हिंदुस्थान में हजारों सालों से रहते आये हुये लोग जिन्होंने आजतक इस देश का इतिहास बनाया है, इस राष्ट्र के पुत्र या स्वामी हो सकते हैं अन्य नहीं।' (गुरू जी समग्र दर्शन खंड –1 पेज 07) गुरु जी वर्तमान राष्ट्र जिसमें सभी धर्म और पंथ रहते हैं उसे 'भानुमती का कुनबा बताते हैं। उनका कथन है कि 'ऐसे ही, कहीं की ईट कहीं का रोडा भानुमती ने कुनबा जोडा' जैसी जोडतोड से राष्ट्र नहीं बनते। (विजय कुमारः बोध कथाः सुरुचि प्रकाशन पेज 34) एक और जिम्मेदार संघी बाबासाहब भिड़े का मुसलमानों से कहना है कि 'अपने आप को योग्य सिद्ध करने के लिए आपको तमाम मस्जिदें तोड़ देनी चाहिए और उनके स्थानों पर मंदिर बनवाकर हमें सौंप देना चाहिए–यह संघ का उद्देश्य है। संघ इस उद्देश्य की प्राप्ति की तैयारी कर रहा है। यह सब बातें मैं संघ के एक जिम्मेदार व्यक्ति की हैसियत से कह रहा हूँ।' (उद्धृत पी वी पराकलः मासिक कम्युनिस्ट अंक 7 –1979 पेज 55)

सँघ साहित्य में ऐसे दर्जनो धमकी भरे दादागिरी भरे उदाहरण और कई कथन मिलेंगे जो देश मे कुछ खास समुदायों के प्रति नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं और सदियों से विकसित मिलीजुली गंगा जमुनी संस्कृति को समाप्त करने की बात करते है यानी वे विभाजनकारी प्रवृत्तियों के पोषक हैं।

क्या मोदी, राजनाथ, नड्डा, मोहन भागवत, सँघी दिग्गज यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि जो लोग उक्त सोच रखते है, गलत थे और हैं तथा देश के लिए घातक हैं? आजतक गोलवलकर के ऐसे विचारों को किसी भी सँघ प्रमुख या सँघ उत्पादों ने नकारा नही है आखिर क्यों? बात बिकुल साफ है मुंह में राम, बगल में छुरी। और यह राम और छुरी का अभियान सरकारी गैर सरकारी माध्यमों और गोदी मीडिया द्वारा अनवरत चलाया जा रहा है। जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है।

जी–20 शिखर सम्मेलन का आयोजन

गुटनिरपेक्षता से लेकर वैश्विक शांति और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे एजंडे में शामिल हों

डॉ. अरुण मित्रा

अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाली जी–20 बैठक को लेकर काफी उत्साह पैदा किया जा रहा है, विशेष रूप से यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही भारत को समूह की अध्यक्षता मिली है, तथा इसी का प्रचार जोर–शोर से किया जा रहा है। परन्तु मामले की सच्चाई यह है कि जी–20 में अध्यक्षता की एक चक्रीय प्रणाली है, जिसके तरह सभी सदस्य देशों को बारी–बारी से आयोजन का अवसर और अध्यक्षता और दी जाती है। दरअसल भारत पिछले साल जी–20 का अध्यक्ष बन सकता था लेकिन इसमें एक साल की देरी हो गयी।

जी–20 के पास चर्चा के लिए कई एजेंडे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक शांति और सभी के लिए स्वास्थ्य है। कई हिस्सों में चल रहे सशस्त्र संघर्षों के कारण आज दुनिया बहुत गंभीर स्थिति में है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इस समय सबसे गंभीर है। यूएनओ के अनुसार अब तक 3604 नागरिकों सहित 14400 से अधिक लोग मारे गये हैं। 80 लाख से अधिक लोग बाहरी रूप से विस्थापित होकर दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।

मामला सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रह गया है। अमेरिका और नाटो की स्पष्ट भागीदारी से चीजें बहुत आगे बढ़ गयी हैं। दोनों पक्षों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बयान जारी करने के बाद कि वह यूक्रेन को क्लस्टर हथियारों की आपूर्ति करेंगे, रूस ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में उनके पास परमाणु हथियारों का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। यह बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि इस समय उस सीमा पर कोई भी परमाणु आदान–प्रदान रूस और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रहेगा। यह रूस और अमेरिका और नाटो के बीच परमाणु आदान–प्रदान होगा। नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसका मतलब 5 अरब से अधिक लोगों की मृत्यु होगी जो हजारों वर्षों के मानव श्रम के माध्यम से निर्मित आधुनिक सभ्यता का अंत होगा।

आईपीपीएनडब्ल्यू और पर्यावरण समूहों द्वारा किये गये अध्ययन ने पहले ही सुबूतों के साथ दिखाया है कि उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित परमाणु आदान–प्रदान से भी 2 अरब से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन रूस और अमेरिका के बीच आदान–प्रदान कहीं अधिक विनाशकारी होगा।

इसके अलावा अफ्रीका और एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी संघर्ष चल रहे हैं। इन आंतरिक झगड़ों को अमीर देशों के विभिन्न आर्थिक हितों के लिए किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है। फिलिस्तीन या सीरिया की स्थिति अत्यधिक मानवाधिकार उल्लंघन के उदाहरण हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जी–20 परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर कड़ा निर्णय ले और छोटे हथियारों के प्रसार पर रोक लगाये।

हालाँकि यह असंभावित सा लगता है क्योंकि जी–20 एक समरूप समूह नहीं है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों और सैन्य औद्योगिक परिसरों पर हावी स्व–हित वाले देशों का एक समूह है। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) के विपरीत है जिसने प्रभावी कदम उठाये और विभिन्न देशों में निरस्त्रीकरण, विकास और मानवाधिकारों के मुद्दे पर गंभीर चिंताएँ उठायीं। यह सर्वविदित है कि उस समय भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नैम की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और अब्दुल गमाल नासिर की पहल पर की गयी थी। नैम का 7वाँ शिखर सम्मेलन 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें 117 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और कई देशों के 20 पर्यवेक्षक थे।

इसके विपरीत, जी–20 एक छोटा आयोजन है लेकिन बहुत अधिक प्रचार के साथ। ऐसा लगता नहीं है कि जी–20 बैठक परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए एक ठोस घोषणा के साथ सामने आयेगी, जो अब 7 जुलाई 2017 को यूएनओ द्वारा पारित परमाणु हथियारों के निषेध पर बहुपक्षीय संधि (टीपीएनडब्ल्यू) के माध्यम से संभव है।

अंदर एक मजबूत लॉबी है। जी–20 ने यूएनओ में टीपीएनडब्ल्यू का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों पर जबरदस्त दबाव डाला। ये देश निवारक के रूप में परमाणु हथियारों के सिद्धांत के नायक हैं। इसकी बहुत कम संभावना है कि जी–20 सभी के लिए स्वास्थ्य पर कोई ठोस निर्णय लेकर आयेगा जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए संसाधनों के समान वितरण की आवश्यकता है।

हमने देखा है कि कैसे फार्मास्युटिकल कंपनियों, विशेष रूप से वैक्सीन उत्पादक कंपनियों ने कोविड महामारी के दौरान तबाही मचायी और छोटे देशों को ब्लैकमेल किया, जिनके पास अपने दम पर वैक्सीन बनाने के लिए न तो तकनीकी जानकारी थी और न ही संसाधन। माना जाता है कि बड़ी फार्मा कंपनियों ने इस अवधि के दौरान भारी मुनाफा कमाया है। सभी के लिए स्वास्थ्य, सस्ती दवा मूल्य निर्धारण और न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल पर किसी भी बातचीत के लिए, फार्मा कंपनियों को विनियमित करना होगा और उनके मुनाफे को पारदर्शी बनाना होगा।

जी–20 की गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों में नतीजों पर नजर रखना अच्छा रहेगा। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश कॉर्पोरेट समर्थक विचारधारा और आर्थिक हितों वाले हैं।क्या वे हथियार छोड़ने के लिए तैयार होंगे या क्या वे विश्व व्यापार संगठन में प्रभावी बदलाव करने के लिए तैयार होंगे ताकि विकासशील देशों की सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके?

7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत ने विकासशील देशों को निरस्त्रीकरण, समान विकास, मानवाधिकार, सभी के लिए स्वास्थ्य आदि एक लक्ष्य पर संगठित करने में बड़ी भूमिका निभायी थी। उन्होंने फिलिस्तीनियों के हितों और मानवाधिकारों के अन्य मुद्दों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किये थे। ऐसे फैसलों के लिए स्टेट्समैनशिप की जरूरत होती है। वर्तमान में हमारी राजनीति में उस स्तर के राजनैतिक कौशल का अभाव है। (संवाद)

सरकार ने आधा दर्जन अमेरिकी प्रोडक्ट्स से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई: राष्ट्रपति बाइडेन के भारत आने से पहले लिया फैसला, जून 2019 में 120% तक बढ़ा दी थी ड्यूटी

राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने से पहले भारत सरकार ने बादाम, सेब, अखरोट और दाल जैसे करीब आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। जून 2019 में सरकार ने अमेरिकी अखरोट पर 30% से 120% तक और चना, मसूर दाल पर 30% से 70% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में ऑफिशियल अमेरिकी यात्रा पर दोनों देशों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) में छह विवादों को खत्म करने और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क को हटाने का फैसला लिया था। जो बाइडेन जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने शुक्रवार को भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाइलेटरल मीटिंग भी करेंगे।

बता दें कि जुलाई में उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि सरकार ने सूखे, ताजे, छिलके वाले बादाम, अखरोट, चना, मसूर और सेब पर जवाबी शुल्क हटाने का फैसला किया है। इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। बता दें कि सरकार के इस फैसले से इन उत्पादों की कीमतों पर भी असर नहीं होगा।

इन उत्पादों पर से हटाई गई ड्यूटी: सरकार के इस फैसले के बाद चना पर 10%, मसूर दाल पर 20%, ताजे या सूखे बादाम पर 7 रुपए प्रति किलो ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा छिलके वाले बादाम से 20 रुपए प्रति किलो, छिलके वाले अखरोट से 20% और सेब से 20% ड्यूटी हटाई गई है।

सरकार ने 2019 में लगाई थी 120% तक इंपोर्ट ड्यूटी: भारत ने 2019 में अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले 28 प्रोडक्ट्स पर 120% तक ड्यूटी लगाई थी। सरकार ने यह फैसला तब लिया था, जब अमेरिका ने भारत के एल्युमीनियम और स्टील प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ा दी थी। इसे रीटेलिएटरी या जवाबी शुल्क भी कहा जाता है।

एबीसी ने भारत के फैसले का स्वागत किया: आमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया (एबीसी) ने भारत के इस कदम का स्वागत किया है। एबीसी ने स्टेटमेंट में कहा कि भारत के इस फैसले से छिलके वाले अखरोट के शिपमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी 35 रुपए प्रति किलो और कर्नेल (कॉर्न) का 100 रुपए प्रति किलो हो जाएगी।

भारत ने जुलाई में नॉन–बासमती के एक्सपोर्ट पर लगाया था बैन: जुलाई में सरकार ने नॉन–बासमती व्हाइट राइस (सफेद चावल) के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। देश में चावल की कीमतों में तेजी को रोकने और डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था। इस बैन से दुनिया भर में चावल की कीमतें 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं। इसके बाद अमेरिका में कई जगहों पर लोगों को चावल के लिए लंबी लाइनों में घंटों खड़े देखा गया था।

आईएमएफ ने कहा था– बैन हटाने के लिए भारत से बातचीत करेंगे: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) कई बार कह चुका है कि वह भारत से चावल की कुछ निश्चित किस्मों के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए बातचीत करेगा। भारत के एक्सपोर्ट बैन करने के फैसले से दुनियाभर में चावल की कीमतों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका मतलब यह कि दुनियाभर में महंगाई बढ़ रही है।

मोदी सरकार और उसकी विनाशकारी नीतियों से मुक्ति के अभियान का समय

विद्यासागर गिरि

देश के केंद्रीय श्रम संघों और संयुक्त किसान मोर्चा के कन्वेंशन में स्वीकृत 24 अगस्त का ऐतिहासिक संयुक्त घोषणापत्र में विगत 9 वर्षों से सत्ता पर कब्जा जमाये बैठी भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताते हुए और **'देश बचाओ–जनता बचाओ'** का नारा देते हुए 2024 में देश को मोदी–शाह जोड़ी की विनाशकारी नीतियों वाली हुकूमत को सत्ता से हटाने का अभियान तेज करने का आह्वान किया गया था। दूसरी तरफ मुम्बई में इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को सम्पन्न तीसरी बैठक, नये विकल्प का ढांचागत सांगठनिक चार महत्वपूर्ण समितियां को बनाने के साथ **'जुड़ेगा भारत–जीतेगा इंडिया'** के नारे के साथ उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। मजदूर–किसान संयुक्त सम्मेलन और 'इंडिया' गठबंधन की तीसरी बैठक के नारों **"2024 में मोदी सरकार हटाओ–देश बचाओ"** की पृष्ठभूमि में आयोजित जी–20 सम्मेलन के भारी सफलता के आत्ममुग्ध प्रचार के बाद भी सत्ताधारी खेमे में एक घबराहट और भय का सा माहौल दिख रहा है।

जी–20 बैठक में दिल्ली में लॉकडाउन और यथार्थ को छिपाने के लिए 16 झोपड़पट्टियों में कपड़ों का घेरा और आईजीआई एयरपोर्ट से अतिथियों के ठहरने के होटल तक हर 35–40 मीटर पर और दिल्ली के हर चौक चौराहे पर भारी खर्च से प्रचार हेतु सिर्फ मोदी के फोटो सहित पोस्टर और होर्डिंग्स से पाटकर प्रचार–प्रसार और दिल्ली को मोदीमय बनाकर, लॉकडाउन और कर्फ्यू सा दृश्य बनाकर उसकी सफलता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इस आत्ममुग्धता के साथ **'विश्व गुरू'** बनने की आत्मतुष्टि का एजेंडा का भी पटाक्षेप हो गया, जब जी–20 की अगली मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी'सिल्वा को सौंप दी गई है, जो लैटिन अमेरिका में जनाकांक्षा के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। ब्राजील आज वैश्विक परिदृश्य में परिवर्तन और जनमुखी विकास का प्रतीक के रूप में कार्यरत हैं। भारत के बाद ब्राजील को एक संकेतक के रूप में देखा जाये तो यह भारत के भी उसी दिशा में बढ़ने हेतु मोदी मंडली के पटाक्षेप का द्योतक है।

वास्तव में 2024 से सत्ता में काबिज संघी विचार वाली मोदी मंडली भारत देश की मूल आत्मा पर चोट करने वाली मंडली साबित हुई है। जिसने शब्दजाल बुनकर एवं प्रचारित कर देश को 9 वर्षों में न सिर्फ भारत की समृद्ध विरासत को लहुलुहान किया है, भारत की विरासत एवं 'सर्वे भवन्तु सुखिन' एवं 'अयं–निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्–उदार चरितानामां' को छोड़कर सिर्फ 'वसुधैव कुटुम्बकम' का फर्जी उद्घोष कर लोगों को मूर्ख बनाने एवं कार्पोरेट भक्ति एवं उसकी सेवा के लिए भारत की नींव को हिला रही है। यह मेरा है,

यह तेरा है, यानी सत्तापक्षी एवं अंधभक्तों और विपक्ष की गिनती नीचतापूर्ण ढंग से करके, व्यवहार में घृणा का कारोबार और व्यापार कर "वसुधैव कुटुम्बकम" रटने का मायावी खेल से पर्दा भी उठने लगा है। लोगों में भ्रम के बादल छंटने लगे हैं। उसे और स्पष्ट करने हेतु छदमी प्रचार को बेपर्द कर 'सत्यमेव जयते' का अभियान तेज करने का वक्त आ गया है।

एक तरफ भारत में मोदी मंडली की रखैल सी बन चुकी भारतीय मीडिया जी–20 की सफलता के गुणगान में लगी है, जिसमें विश्व की दो महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्ष चीन और रूस की अनुपस्थिति रही। यह एक तरह से मोदी सरकार के लिए और हमारे देश के वैदेशिक नीति के लिए भी गंभीर विचारणीय प्रश्न है। यह वास्तव में दो बड़े देश द्वारा भारत का या मोदी जी का बॉयकॉट नहीं तो क्या है? सबसे आश्चर्यजनक एवं देश के लिए अपमान का विषय यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ आये अमेरिकी पत्रकारों को खुद उनके राष्ट्रपति से प्रेस वार्ता से रोका गया या अपने ही राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत तक भारत सरकार द्वारा नहीं देने की खबर आई हैं। यह काफी शर्मनाक खबर है। उससे भारत के हर जनतंत्र पसंद लोगों में शर्मिंदगी है। स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से वियतनाम जाकर जो प्रेस बयान दिया है वह भारत के लिए भी भारी अपमान नहीं तो क्या है? भारत से वियतनाम जाकर बाइडेन ने कहा कि हमने बैठक में मानवाधिकार, नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस के प्रति सम्मान का मुद्दा उठाया जैसा कि हमेशा कहता हूं।

यानी भारत में जो बाइडेन यह बात नहीं बोल सके तो वियतनाम में जाकर बोले। चार लाइन का बाइडेन का बयान हमारे आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री और भारत के बेशर्म मीडिया के लिए एक बड़ा तमाचा नहीं तो क्या है?

सीएनएन ने समाचार छापा कि भारत में अमेरिकी प्रेसिडेंट को प्रेस से संवाद करने से रोका गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर टिप्पणी की है कि मोदी जी का नारा है–न प्रेस कांफ्रेंस करूंगा–न प्रेस कांफ्रेंस करने दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रांस में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि **"वर्तमान हुकूमत में भारत की आत्मा पर आघात किया जा रहा है। इस दौर में कानून का राज नहीं सत्ता की तानाशाही है। संस्थानों को जड़ से खोखला कर दिया गया है अगर सत्ता में आये तो बक्शा नहीं जायेगा।"**

इससे मोदी सत्ता एवं संघी जमात में बेचैनी देखी जा रही है। अंधभक्तों की टोली एवं भाजपा के वाचालों की सियार संस्कृति यानी जब एक सियार बोलता है तो सब 'हुआ' – 'हुआ' करने लगता है के अंदाज में धार्मिक एवं राष्ट्रीय भावना भड़काने वाला अक्रामक बयानबाजी के साथ घबराहट में और उतावलेपन में सारी हदें पार करते हुए 'कुछ भी कर गुजरने' जैसी स्थिति बनाई जा रही है। उसी कड़ी में संसद का विशेष सत्र 18 से 22 को बुलाना, एक देश एक चुनाव की बातें, सनातन धर्म और हिन्दू धर्मोंमाद उभारने, राम मंदिर निर्माण एवं उद्घाटन कार्यक्रम को राष्ट्रीय अभियान बनाकर और भावना को भुनाने और यहां तक कि बौखलाहट में 'इंडिया' शब्द को ही प्रयोग से रोककर 'भारत' नाम बदलने का अभियान का प्रारंभ उनके अंदर की घबराहट का प्रतिबिंबन है।

मजदूर किसानों का संयुक्त सम्मेलन में सत्ता से मोदी सरकार को हटाने का अभियान, 'इंडिया' गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव एलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई और दोनों में 2024 में भाजपा को हटाने के लिए संकल्प के साथ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय काफी महत्व रखता है। इंडिया गठबंधन में चार महत्वपूर्ण समितियों का गठन सर्वसम्मति से होने और **"जुड़ेगा भारत जीतगा इंडिया"** का नारा मोदी और संघ मंडली में बेचैनी का पराकाष्ठा पर पहुंचा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जिस तरह अपने 9 वर्षों के शासन में देश में भय और दहशत का साम्राज्य बनाकर देश के सारे संवैधाानिक संस्थानों को गुलाम सा उपयोग कर और भारत में संविधान, कानून एवं मानवीय संवेदनायुक्त शासन व्यवस्था की जगह घोर तानाशाहीयुक्त, एक व्यक्ति की इच्छा का शासन की स्थिति बनायी है, उसका अंत सन्निकट है। पूरी संघी मंडली और कार्पोरेटों के चाकर भयाक्रांत हो चुके लगते हैं।

उन लोगों के भयाक्रांत होने का कारण भी स्पष्ट है कि वे सिर्फ 37% मत पाकर वर्तमान चुनाव प्रणाली में अपने भारी संख्या बल से जीतकर बहुमत प्राप्त किये हैं और उसका नीचतापूर्ण दुरूपयोग का रिकार्ड भी इस दौर में बनाया है। वही उन्हें भयाक्रांत कर दिया है। 63% विरोध पक्ष अगर एकजुट हो रहा है, और 9 वर्षों में उनकी छद्मी सृजित आभा का क्षरण और चेहरे से नकाब हट रहा है, भयंकर और भारी भ्रष्टाचार के खुलासे, कालाधन, राफेल डील, पनाम पेपर दबाने के बाद भी हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी (आर्गनाइज्ड क्राइम एंड क्रप्शन रिर्पोटिंग प्रोजेक्ट यानी संगठित अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रतिवेदन की परियोजना) द्वारा मोदी शासन में अडानी के रिकार्ड तोड़ भ्रष्टाचार का उजागर होना, जम्मू–कश्मीर में घोटाले का खुलासा, स्मृति ईरानी के मंत्रालय में स्कॉलरशिप के सैंकड़ों करोड़ के भारी घोटाले का खुलासा, सड़क निर्माण में कई गुणा ज्यादा दर पर टेंडर और पैसे के बल पर गंदी और घृणित राजनीति, इलेक्टोरल बौंड के माध्यम से हजारों–करोड़ की गुप्त चंदा प्राप्ति, 8 लाख करोड़ रूपये का कार्पोरेट टैक्स छूट तेरह लाख करोड़ का कार्पोरेट बैंक ऋण माफी, हजारों, लाखों, करोड़ों के सार्वजनक क्षेत्र के उद्यम, एयरपोर्ट, बंदरगाहों को अपने चहेतों को सुपुर्दगी सहित इनके ऊंचे दर्जे के भ्रष्टाचार पर से उठ रहा पर्दा सहित आजाद भारत में ऐतिहासिक भ्रष्टाचार के कुछ खुलासे ने इनकी नींद हराम कर दी है। सत्ता संस्थानों का आतंक, डर एवं दहशत के माहौल में भी इनके कुछ खुलासे करने वालों पर दमन चलाने एवं सारे सूचना तंत्र और जनतंत्र की मूल आत्मा को ही बंधक बनाकर तानाशाहीपूर्ण राजनीति के खुलासे से इनकी बौखलाहट देखने लायक है।

संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन और मोदी के जन्मदिन पर 13 हजार करोड़ की विश्वकर्मा योजना का प्रचार अभियान में सारे 70 मंत्रियों को देशभर में प्रचार का निर्देश और मनुस्मृति तथा वर्णवादी व्यवस्था के पक्षधर ब्राह्मणवादी वर्चस्व के सिद्धांतकार मोहन भागवत का पिछड़ों और आरक्षण के पक्ष में बयानबाजी के साथ एक बार फिर से 'सनातन धर्म' और 'हिन्दू धर्म' के स्वतः ठेकेदार बन उस पर उन्मादी बयानबाजी, इनके फूहड़पन और घबराहट के उदाहरण हैं।

ये सत्ता से हटने की संभावना से इस कदर दहशत में आ चुके हैं कि अपने सारे विश्वंशक एजेंडा को वर्तमान बहुमत काल में सारी प्रक्रिया, परंपरा और नीति को ताक पर रखकर तहस–तहस कर डालना चाहते हैं, जो एक खतरनाक संदेश है। दो राज्यों और मध्यावधि चुनावों में हार के बाद हो रहे 5 राज्यों के चुनाव के पूर्व 'एक देश एक चुनाव' का नारा और उसके लिए एकतरफा कमेटी का गठन, उसके पूर्व संसद का बिना एजेंडा का 5 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन एवं जी–20 के बहाने सिर्फ मोदी–मोदी के पोस्टरों एवं बैनरों से दिल्ली को पाटकर और झोपड़ी के गरीबों को ढककर मोदी की छद्मी प्रचारात्मक छवि निर्माण के सहारे "राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली" की तरह व्यक्ति केंद्रित राजनीति को खतरनाक ढंग से बढ़ाने का खेल चरम पर पहुंच चुका है। यह घबराहट में सत्ता दुरूपयोग का बढ़ता हुआ दीपक की लौ इनके बुझने की स्थिति का झल्लाहट जैसी प्रतीत होती है।

ऐसी परिस्थिति में जन हितैषी, जनतंत्र हितैषी संविधान और न्याय हितैषी जन–गण और मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवियों और सारे मेहतनकश लोगों का परम कर्तव्य है कि "शहीदे आजम भगत सिंह" के जन्म माह 23 सितंबर में शहीद भगत सिंह के उस विचार को असली रूप देने में जुटे– जिन्होंने कहा था **"जन्म सिद्ध अधिकारों को पद दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है"।** आइए, शहीद भगत सिंह का संदेश को अंगीकार करें और इस कर्तव्य का पालन करने में पूरी शक्ति से जुट जाये। संविधान, जनतंत्र, मानवता और मानवीय संवेदना को धुल–धुसरित करने वाली मोदी हुकूमत को सत्ता से उखाड़ फेंकने के अभियान में जुट जायें। मोदी शासन के झुठ, फरेब, जुमलेबाजी और छद्मी धार्मिक–राष्ट्रवादी नकाब को उतारकर, असत्य पर सत्य की विजय पताका फहराने हेतु जनता के बीच उनके अनुभवों को याद दिलाने का अभियान अनवरत जारी रखें।

2014 से 2023 के बीच में मोदी सरकार और खासकर नरेन्द्र मोदी के शासन में आने के पूर्व उस जुमले वाले वायदे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी, महंगाई पर लगाम, भ्रष्टाचार पर रोक एवं काला धन लाकर 15 लाख रूपये सबके खाता में देने, सबका साथ –सबका विकास कह सबका सर्वनाश करने, देश के राष्ट्रीय संपदा को लूटने–लुटाने, मजदूरों के श्रम अधिकार वाले कानूनों को कोड में बदल उन्हें बंधुआ मजदूर या पूंजी का आधुनिक गुलाम बनाने, किसानों पर बेरहम हमला और वायदा खिलाफी, सारे संवैधानिक संस्थानों का नीचतापूर्ण दुरूपयोग, जनतंत्र, संविधान, नागरिक आजादी, प्रेस और सूचना की आजादी, सब पर अपूर्व खतरा पैदा करने, कार्पोरेटों को लूट की छूट और जनता की जीएसटी से लूट और सबसे खतरनाक ढंग से भारत की सांझी सांस्कृतिक विरासत और उच्च स्तरीय शिक्षा पाठ्यक्रम और इतिहास को बदलकर, अंध–धार्मिक उन्माद, जातीय साम्प्रदायिक हिंसा के सहारे गंदी राजनीति और भारत की आत्मा की हत्या के कुकृत्य वाली जमात को राष्ट्रहित में सत्ता से हटाने तक बिना विश्राम अभियान तेज करें।

एटक की राष्ट्रीय सामान्य परिषद की बैठक कोयम्बटूर के त्रिपुर में 21 से 23 सितंबर को होने वाली है। उसमें आगामी घोषित आंदोलनों को मूर्त रूप देने एवं देश में जनतंत्र, नागरिक अधिकार, संविधान और सर्वधर्म समभाव और साझी सांस्कृतिक विरासत को हर हाल में अक्षुण्ण रखने हेतु – जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी हुकूमत को सत्ता से हटाये बगैर विश्राम नहीं करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ें।

कुशीनगर खेत मजदूर यूनियन का जिला सम्मेलन

खेत मजदूर जागेगा तो पूरा देश जागेगा

कुशीनगर, 02 सितम्बर 2023: उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन का चौथा जिला सम्मेलन राम नरेश पाल व जोगिना देवी दो सदस्यों के अध्यक्षमंडल की अध्यक्षता में संकट मोचन मंदिर धर्मशाला तमकुही राज, कुशीनगर में 02 सितम्बर 2023 को सम्पन्न हुआ। उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन के महासचिव फूलचन्द यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी खेत मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, जनजातियों, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गयी है आज भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाये हैं, उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, जोतने के लिए जमीन नहीं है, पीने के लिए शुद्व पानी नहीं है, शिक्षा की कोई गारण्टी नहीं है, मंहगाई और विस्थापन की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, इनके लिए आज तक कोई केन्द्रीय कानून नहीं बना, जो भी कानून हैं उनको लागू करने की शासन व प्रशासन की मंशा बहुत ढ़ीली व लचर है। मुल्क में जितनी भी दलित, आदिवासी और जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार एवं छेड़छाड़ की घटनाएं हुयी हैं उसमें उ. प्र. पहले नम्बर पर है कोई भी महिला जब घर से बाहर मजदूरी के साथ निकलती है तो इस बात का अन्देशा लगातार बना रहती है कि सुरक्षित वापस आ पायेगी की नहीं। जंगलों में रहने वाली महिलाओं की हालत तो और बदतर है जंगली लकड़ियों के लिए अफसरों व ठेकेदारों द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जा रहा है उनका जीवन इतना कठिन है कि कल की रोजी रोटी के डर से किसी सक्षम अधिकारी तक शिकायत भी नहीं कर सकती। मोदी, योगी सरकार में मजदूरों का पलायन बहुत तेजी से हुआ है, उनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं है दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं उनकी सुरक्षा की भी कोई गारण्टी नहीं है। खेत मजदूरों के सामने आखिरी विकल्प है कि या तो लामबन्द होकर अपने वजूद को बचाने के लिए निर्णायक संघर्षो के लिए तैयार रहें या अपने को समाप्त कर लें।

यूनियन के महासचिव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार साल दर साल मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है जैसे–जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है वैसे–वैसे बजट में कटौती बढ़ती जा रही है। योगी सरकार में सैकड़ों साल से बसे हुए मजदूरों को बिना नोटिस बुलडोजर चलाकर उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है खुले आसमान के नीचे परिवार के साथ हर मौसम के थपेड़े बर्दाश्त करने को मजबूर हैं कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। मनरेगा में साल भर में केवल 27 दिन काम मिल पा रहा है अधिकांश मजदूर रोजगार विहीन हैं, पुलिस जुर्म, भूमाफिया का शोषण अलग से झेलना पड़ रहा है। फूलचन्द यादव ने खेत मजदूरों को को ललकारते हुए कहा कि हमारी संख्या देश में सबसे बड़ी है, देश के सकल उत्पादन में हमारा सबसे बड़ा योगदान है, देश को यहाँ तक पहुंचाने में हम खेत मजदूरों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जिसको अपने खून पसीने से सींचा है उस देश और संविधान को बचाने की महती जिम्मेदारी हम लोगों के उपर आन पड़ी है, पूरा साम्प्रदायिक, फासीवादी, पूंजीवादी सिस्टम ही हमारे कन्धों पर खड़ा है सिर्फ कन्धा हिलाने की आवश्यकता है पूरा का पूरा सिस्टम भरभरा कर गिर जायेगा। आप जगोगे–पूरा देश जागेगा।

सम्मेलन के अन्त में एक 11 सदस्यीय जिला कौंसिल का चुनाव किया गया। जिसके रामनरेश पाल अध्यक्ष, रामचन्द्र यादव व सरल प्रसाद भारतीय उपाध्यक्ष, सुदामा यादव जिला महामंत्री, राम प्रवेश व जय प्रकाश मंत्री चुने गये।

सम्मेलन का समापन भाकपा जिला मंत्री मतिउल्ला एडवोकेट ने किया। संचालन सुदामा यादव ने किया।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के लिए मीटिंग

ईरोडः भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तमिलनाडु राज्य कार्यकारिणी और जिला सचिव और जिला अध्यक्ष की बैठक 23 अगस्त 2023 में ईरोड संगठन के दफ्तर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष एन पेरियासामी ने की।

राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य पी गणेशन ने शोक प्रस्ताव रखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव आर मुतरासन ने वर्तमान राजनीति के हालात पर रोशनी डाली।

बीकेएमयू के तमिलनाडु राज्य महासचिव ए भास्कर ने राज्य के 13वें अधिवेशन के आह्वान पर मनरेगा परियोजना में 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने के लिए गाँव यूनिट से 1091 ग्रामसभा की बैठकों में एक याचिका प्रस्तुत थी। उन्होंने इस के बारे में विस्तार से बताया और अधिवेशन के बारे में एक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। जिस पर 31 सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया। अंत में विभिन्न सुझावों रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

राज्य सम्मेलन के बाद पूरे तमिलनाडु में संगठन की गतिविधियों में प्रगति हुई है। समिति ने राज्य सम्मेलन को बहुत अच्छे ढंग से आयोजित करने के लिए सीपीआई विरुदुनगर जिला समिति और बीकेएमयू की जिला समिति के प्रति अपना आभार और सराहना व्यक्त की है।

राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य पी गणेशन ने 15वें अधिवेशन के बारे में बताया। सम्मेलन 2023 नवम्बर 2 से 5 तक पटना बिहार में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन 2 नवम्बर को एक रैली के साथ शुरू होगा। जिसमें 5 लाख खेत मजदूर भाग लेंगे। प्रतिनिधि साथियों को रैली की अग्रिम पंक्ति में आना चाहिए। इसीलिए नवंबर एक तारीख की रात को पटना पहुंचने की बात कही गयी।

पी गणेशन

सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि शुल्क 300 रुपये है। सम्मेलन की रिपोर्ट का तमिल में अनुवाद करने पर एक सौ रुपये खर्च आएगा। प्रतिनिधियों को समय पर ट्रेन टिकट बुकिंग करना होगा। इसके विवरण के लिए पी गणेशन से संपर्क करने का निर्णय लिया गया।

राज्य कार्यकारणी समिति के सदस्यों को दिया गया कार्य विभाजन इस प्रकार है।

–पी गणेशन–तिरुचिरापल्ली, तिण्टुक्कल, मदुराई, पेरम्बलूर

–एस महेंद्रन–ईरोड उत्तर, कोयम्बुतूर, नीलगिरी

–ए वर्दराजन–विरुदुनगर, तेंकासी, तिरुनेलवेली, तूत्तुगुडी, रामनादपुरम

–वी पी पल्लनिसामी–तिरुप्पूर, नामक्कल, करूर, तेनी

–जे प्रतापन–तरुमपुरी, तिरुपत्तूर, सेलम, वेलूर

–के मारिमुद्तु (एमएलए)–तिरुवारूर, नागप्पट्टिनम, तंजाऊर दक्षिण

–पी पदमावती–मईलाडुदुराई

–जी वेंकटाचलम–ईरोड दक्षिण

–एस तेवराजन– कृष्णगिरी

–के राजा–तंजाऊर उत्तर

–सी पक्रिसामी–अरियलूर

–ए एल रासु– पुदुकोटाई

–के एस अप्पाऊ – किुप्पुरम, कडलूर, तिरुवण्णामलाई, कल्लकुरुची

–ए भास्कर, एन पेरियासामी–तिरुवल्लूर, सेन्कलपट्टु, कॉजिपुरम, सिवगंगाई, कन्याकुमारी

–सी चंद्रकुमार– राज्य केंद्र

बी श्रीनीवासराव स्मृति दिवस 30 सितम्बर

पूरे तमिलनाडु में जहाँ हमारी यूनियन है उन गाँवों में बी श्रीनीवासराव श्रद्धांजलि देने सभा आयोजित करने और जिला स्तर पर एक आमसभा या सेमिनार या कार्यशाला आयोजित कराने का निर्णय लिया गया।

कोषाध्यक्ष एस चंद्रकुमार ने सदस्यों के पंजीकरण के बारे में जानकारी दी। 2023 साल में तीन लाख सदस्यों का पंजीकरण करावाने का निर्णय लिया गया।

राज्य सम्मेलन के बाद 20 से अधिक जिला समिति की बैठकें हो चुकी हैं। इसे अच्छी प्रगति माना जाता है।

देश को बचाने के लिए सरकार को बदलें

'संविधान बचाओ' बैनर तले बुलाई गई एक सार्वजनिक बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिव अजीज पाशा ने वर्ष 2024 में आगामी लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का जोरदार आह्वान किया।

अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय सचिवमंडल सदस्य अजीज पाशा ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता में आई वर्तमान भाजपा सरकार मजबूत तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था वाली सरकार है। वह तमाम ऐसे फैसले ले रही है जो जनविरोधी और संविधान की भावना के खिलाफ हैं। आपातकाल की घोषणा किए बिना केंद्र सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है मानो संसद में कोई विपक्ष ही नहीं है। अजीज पाशा ने चंतावनी दी कि विपक्ष के अभाव में, भारत में लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा।

'चंद्रयान मिशन' की सफलता का ताजा उदाहरण देते हुए अजीज पाशा ने कहा कि भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनाने के लिए हम सभी को इसरो के अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। जब पाशा ने कहा कि यह आदमी इतना आत्म–मुग्ध है कि, वह इसरो की कड़ी मेहनत का सारा श्रेय खुद लेना चाहता है, तो दर्शक हंस पड़े। वो इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि यह मोदी ही थे जिन्होंने चंद्रयान के सभी संचालन को नियंत्रित किया था। पाशा ने कहा कि यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से अनैतिक है। स्वतंत्रता संग्राम में कभी भाग नहीं लेने के कारण, आरएसएस कभी भी भारत के संविधान की भावना

डॉ. युगल रायलु

को समझने में सक्षम नहीं है, और इसलिए वे नियमित रूप से इस महान संविधान को कमजोर करते रहते हैं। इस महान देश के सामान्य नागरिक को सभी अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करना भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। नागरिकों के रूप में हमारा कर्तव्य चुनाव के दिन वोट डालने से भी आगे जाना चाहिए। इस महान देश को तानाशाहों से बचाने के लिए हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए।

अजीज पाशा ने ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि हमारे देश और उसके संविधान को बचाने का सबसे अच्छा तरीका अगले लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराना है।

आरपीआई (सेक्युलर) के अध्यक्ष श्याम दादा गायकवाड़ ने आम लोगों से संकट की इस घड़ी में एक साथ आने का आह्वान किया ताकि हम महान लोकतंत्र को बचा सकें। यह समय राजनीतिक मतभेदों पर चर्चा करने का नहीं है। यह समय एकजुट होने का है। जाने माने अनुभवी बुद्धिजीवी प्रोफेसर रणजीत मेश्राम, प्रोफेसर शशि सोनोने, श्री बादल सरोज ने भी सभा को संबोधित किया।

अशोक सरस्वती ने कार्यक्रम का मुख्य–नोट प्रस्तुत किया जबकि भाकपा के नगर जिला सचिव अरुण वनकर ने मोदी शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का प्रस्ताव पेश किया। भाकपा (मा) के नागपुर जिला सचिव अरुण टाकर ने बढ़ती साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जयश्री चाहांदे ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई। जम्मू आनंद, श्री चन्द्रशेखर शेंडे और सुश्री प्रमिला सोनोने ने कार्यक्रम की कार्यवाही का संचालन किया।

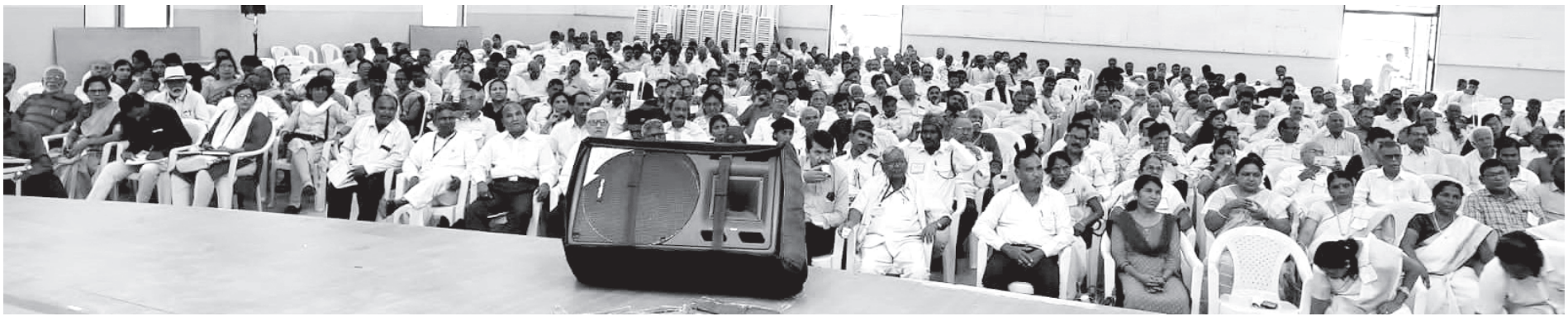

देश पर बढ़ता विदेशी कर्ज चिंता का विषय

पटना, 11 सितम्बर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि देश पर बढ़ता विदेशी कर्ज चिंता का विषय है। मोदी सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। 31 मार्च 2023 तक भारत पर 155 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। कर्ज की राशि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। कुल कर्ज में 79.4 फीसदी लंबी अवधि का कर्ज है।

भाकपा राज्य सचिव ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में देश पर 181 फीसदी कर्ज बढ़ा है। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपये था। 2014 तक तीन गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपये हो गया जबकि नौ वर्षों में कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में एक सौ लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि यह कर्ज केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लगातार कटौती और राज्यांश बढ़ाने के बावजूद बढ़ते जा रहा है। केंद्र सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण लगातार कर्ज की राशि बढ़ रही है। मोदी सरकार एक तरफ लोक कल्याणकारी योजनाओं की राशि में कटौती कर रही है तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों को विभिन्न करों में छूट दे रही है। वहीं फिजूलखर्ची भी ज्यादा कर रही है। पिछले नौ वर्षों में बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के बाबजूद केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई, भूखमरी, गरीबी, अभाव, कुपोषण, बेरोजगारी बढ़ी है। इस सरकार से देश की जनता तबाह है। जनता को बुनियादी जरूरत के खर्चों में भी कटौती करनी पड़ रही है। यह सरकार आरएसएस के एजेंडों को लागू कर रही है। आर्थिक सुधार के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कौड़ी के भाव में बेच रही है और अपने पूंजीपति मित्रों अडानी और अंबानी को दे रही है।

भाकपा ने किया मस्तुरी विधानसभा लड़ने का फैसला

बिलासपुरः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद सदस्यों की बैठक 10 सितम्बर 2023 को शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर देवरीखुर्द भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में रखी गई। जिसकी अध्यक्षता उदय राम टंडन जी ने की। मीटिंग में सर्वसम्मति से मस्तुरी विधानसभा से लक्ष्मण टंडन को अपना प्रत्याशी घोषित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक वैचारिक पार्टी हैं जो नीतियों और विचारों पर चुनाव लड़ेगी। 27 सितम्बर 2023 को मस्तूरी ब्लाक में जन समस्या को लेकर रैली कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

मीटिंग में निम्न बातों पर भी विचार किया गया। भारत देश की अभी की परिस्थितियों में जो स्थिति बनी हुई है जगह–जगह धार्मिक उन्माद हो रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसको लेकर गहन विचार विमर्श किया गया एवं इस परिस्थिति से हमारे देश को निकालने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर विचार किया गया। मीटिंग में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव पवन शर्मा, कांशीराम ठाकुर, विक्रांत, भैरव चंद्र निषाद, चिल्लू सिंह, एचडी पाइक, पॉवेल, संत निराला, धीरज शर्मा, सुखलाल गड़ेवाल, दिलीप धूरी, कन्हैया लाल यादव आदि साथी उपस्थित थे।

पार्टी शिक्षा पर एक कार्यशाला

सुबोध दत्ता

कोलकत्ता: आज जब देश गहरे संकट में है ऐसे समय में भाकपा के राज्य पार्टी शिक्षा विभाग ने 26 और 27 अगस्त को कोलकाता के भूपेश भवन में पार्टी शिक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

केंद्र में आरएसएस नियंत्रित और कारपोरेट संचालित सांप्रदायिक फासीवादी भाजपा सरकार देश को धर्म, लिंग, भाषा, जाति और समूहों पर आधारित बंटवारे की ओर धकेल रही है।

वे हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस गहरे संकट से मुक्ति पाने के लिए कम्युनिस्टों को मार्क्सवादी–लेनिनवादी शिक्षा की आवश्यकता है। पार्टी के केंद्रीय शिक्षा विभाग के प्राचार्य अनिल राजिमवाले ने 26 अगस्त को कार्यशाला के उद्घाटन भाषण में यह राय व्यक्त की। कम्युनिस्ट आंदोलन का मुख्य आधार आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई। आरएसएस और कारपोरेट पूंजी से निर्देशित सरकार देश के संसाधनों का निजीकरण कर पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है।

देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी शिक्षा बहुत जरूरी है। अत: संबंधित पम्फलेट्स, बुकलेट्स और किताबों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है।

'पार्टी शिक्षा का महत्व एवं भावी योजनाएं' विषय पर आयोजित की गयी कार्यशाला में राज्य सचिव स्वप्न बनर्जी ने कहा कि देश गहरे संकट से गुजर रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में मार्क्सवादी–लेनिनवादी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज की राजनीति और भी जटिल होती जा रही है। इस जटिल राजनीति को समझने के लिए अधिक से अधिक कार्यशालाओं की आवश्यकता है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद में शिक्षित कैडर कम्युनिस्ट पार्टी की असली संपत्ति होते हैं।

इस अवसर पर कालांतर के संपादक कल्याण बनर्जी और श्रीकुमार मुखर्जी ने भी अपने विचार रखे।

भाकपा अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है। भाकपा को मुडकर लोगों को दिशा दिखानी होगी। दो दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन इस आह्वान को महत्व मिला। दिन के वक्ता थे राज्य पार्टी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल, भानुदेव दत्ता, केंद्रीय सचिवमंडल सदस्य, पल्लब सेनगुप्ता और न्यू एज की सहायक संपादक, कृष्णा झा। भानुदेब दत्ता ने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन मूल रूप से मजदूरों और किसानों का आंदोलन है। कम्युनिस्ट इस युग का ज्ञान और विवेक हैं।

भाकपा के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य पल्लब सेनगुप्ता ने कहा कि पार्टी को वैचारिक संघर्ष के रास्ते ही आगे बढ़ना होगा।

पार्टी शिक्षा को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए पार्टी शिक्षा विभाग के प्रमुख अमलेन्दु देबनाथ ने राज्य को और उसकी जिम्मेदारियों को पांच भागों में बांटा।

पार्टी शिक्षा की कार्यशाला में जिला और स्थानीय परिषद स्तर पर बड़ी संख्या में पार्टी शिक्षकों ने भाग लिया। चर्चा में 16 जिलों के 23 प्रतिभागियों ने सक्रिय भाग लिया।

पहले दिन कार्यशाला की शुरूआत पार्टी के झण्डे को फहराये जाने और शहीदों को श्रद्धांजलि से हुई।

प्रलेसं: जबलपुर घोषणापत्र

पेज 5 से जारी...

इलेक्ट्रानिक मीडिया के बड़े हिस्से को निष्प्रभावी और पालतू बनाया जा चुका है। सोशल मीडिया भी अब कड़े नियंत्रण में है। 'बिग ब्रदर' की निगहबानी अब तेज है। साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्था का अनुगमन कर वैकल्पिक तथा स्वतंत्र नीतियों वाले राज्य की भूमिका का परित्याग कर दिया गया है। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिये गोरक्षा, लव–जेहाद, हिजाब, गंगा, गीता सरीखे भावनात्मक मुद्दों को उछाला जा रहा है। समाज को धर्म, जाति या निजी विश्वासों के आधार पर विभक्त करने के सारे हथकंडे अपनाये जा रहे हैं, जिस पर सत्ता की तरफ से कोई अंकुश तो दूर, प्रत्यक्ष–परोक्ष समर्थन ही नजर आता है। असहमति और प्रतिरोध की आवाजों को 'अर्बन नक्सल', 'टुकड़े टुकड़े गैंग', 'अवार्ड वापसी गैंग' सरीखे नकारात्मक पदों से लांछित करते हुए, उनके बारे में तमाम झूठ फैलाए जा रहे हैं।

स्वीकार करना होगा कि अब हिंदू पुनरुत्थानवाद एक कार्यसूची (एजेण्डा) की तरह सत्तापोषित केंद्रीय विचारधारा के रूप में सर्वोपरि है। संसद में पुरोहितों द्वारा धार्मिक प्रतीक सेंगोल की स्थापना, फिर अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास में देश की कार्यपालिका के मुखिया की कर्मकांडी भागीदारी इसकी मुखर घोषणा है। देश–विभाजन की त्रासदी को 'विभाजन विभीषिका दिवस' के रूप में उत्सवीकृत कर देश के जनमानस को विभाजन हेतु स्थायी मनोदशा में ढाला जा रहा है। चमत्कारी बाबाओं द्वारा जनमानस को प्रदूषित कर उन्मादी बनाया जा रहा है और शासन–प्रशासन का उन्हें समर्थन प्राप्त है। मणिपुर, मेवात से लेकर उत्तराखंड व देश के दूसरे हिस्सों तक में विभाजन व अलगाव की नयी इबारत लिखी जा रही है। शहरों के नाम बदल कर मिलीजुली पहचान मिटाई जा रही है। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को लव–जेहाद, गोहत्या व जबरन धर्म–परिवर्तन का दोषी करार देकर उनकी शत्रु छवि गढ़ी जा रही है। 'उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या' (लिंचिंग) एवं 'बुलडोजर से न्याय', अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न व दमन के सत्ता संरक्षित नये हथियार हैं। महिलाओं, दलितों या किसानों पर अत्याचार के विरुद्ध अथवा उनके अधिकारों के पक्ष में उठाई जा रही आवाजों की अनदेखी की जाती है और उन्हें कुचला जाता है। राजनीति में बाहुबलियों को संरक्षण है। जो भी समाज के ध्रुवीकरण या समाज को बाँटने वाले बयान देते हैं, उनके ऊपर न्यायालयों के निर्देशों के बावजूद समुचित कार्रवाई न करके उन्हें बचाया जा रहा है। बहुसंख्यकवाद की गर्वीली श्रेष्ठता की मनुवादी वैचारिकी के अनुरूप स्त्रियों, आदिवासियों व दलितों पर अत्याचार और भेदभाव का बढ़ना इसकी स्वाभाविक परिणति है। ऊना, हाथरस से लेकर भीमा कोरेगांव तक यह इबारत पढी जा सकती है। आदिवासियों को उनकी मूल सांस्कृतिक चेतना से उन्मूलित कर जल, जंगल–जमीन की अबाध लूट जारी है, जिसके लाभार्थी अंततः कार्पोरेट पूँजीपति हो रहे हैं जिनका दक्षिणपंथी राजनीति से गहरा गठजोड़ है।

वैचारिक असहमति को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती व संथाली (अंग्रेजी) भाषा के पेरुमल मुरुगन, कांचा इल्लय्या, के. एस. भगवान, एस. हरीश, पारुल खक्कर व हंसदा सोवेंद्र शेखर जैसे रचनाकारों की कृतियों पर बंदिश लगाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शनों से लेकर अदालतों तक का सहारा इस दौर में लिया गया है। ये सारी स्थितियाँ हम लेखकों को आक्रोशित और विचलित करने वाली हैं। इतिहास और पाठ्यक्रम के पुनर्लेखन व पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। अकबर व टीपू सुल्तान सरीखे इतिहास नायकों को बहिष्कृत कर हिंदुत्ववादी नायकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसकी अनिवार्य परिणति के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक संरचना की विविधता, बुनावट की समझ नष्ट होगी और नयी पीढ़ी समावेशी और बहुलतावादी इतिहास की सच्ची जानकारी से वंचित होकर एकांगी, अधूरी और गलत दिशा में जाने के लिए अभिशप्त होगी। एनसीईआरटी की पुस्तकों में आमूलचूल परिवर्तन इसका प्रमाण है। नयी शिक्षा नीति इन परिवर्तनों की दिशासूचक है। हम समझते हैं कि ये सारी स्थितियाँ किसी भी आधुनिक देश, समाज के विकास हेतु सबसे बड़ा अवरोध और खतरा हैं।

विगत लगभग एक दशक में उपरोक्त परिदृश्य के हम अपनी प्रतिरोधी चेतना के साथ साक्षी रहे हैं। समय–समय पर हमने लेखक संगठनों के साझा मंचों से भी अपने प्रतिरोध को दर्ज किया है। किसान आंदोलन, नागरिकता रजिस्टर संबंधी विधिक प्रस्तावों के विरोध, महिला पहलवानों की मुहिम व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, प्रखर पत्रकारिता और बुद्धिजीवियों की आवाजों के पक्ष में हमारी भूमिका समर्थन तथा एकजुटता की रही है। वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में व्यापक जनसंघर्षों के साथ अधिक प्रभावी भागेदारी सुनिश्चित करते हुए संवैधानिक जनतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा आज हमारा पहला दायित्व है। इसके लिए लेखक संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत भी हमारे समक्ष है।

इस संदर्भ में हमें यहाँ प्रेमचंद याद आते हैं, जिन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ स्थापना सम्मेलन के अध्यक्ष पद से आह्वान किया था कि "साहित्य वही है जिसमें जीवन की सचाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों। जिसमें जीवन की आलोचना हो। दलित, पीड़ित, वंचित–चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्य का कर्तव्य है। कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौला जाना चाहिए। हमें सुंदरता की कसौटी बदलना होगी। सौंदर्य की व्यापक परिधि में सारी सृष्टि हो, जो सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता की विरोधी न हो। समाज के साथ ही साहित्यकार का अस्तित्व है, समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य हो जाता है। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश हो, जो हममें गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।" प्रेमचंद के ये उद्गार आज भी प्रासंगिक व दिशासूचक हैं और चुनौतीपूर्ण समय में प्रेरणास्पद हैं। हम इस गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के दावेदार के रूप में सामूहिक रूप से संकल्पबद्ध हैं।

छात्रवृत्ति जारी करने के लिए एआईएसएफ का प्रदर्शन

उदयपुर: ऑल इंडिया स्टुडेंट्स फैडरेशन उदयपुर जिला कमेटी के सदस्यों ने मांगीलाल डामोर और सुरेश मीणा के नेतृत्व में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय पर एक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में मांग की गई कि उदयपुर में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों को विभाग से मिलने वाली वर्ष 2023 की छात्रवृति विभाग नेअभी तक नहीं दी है इससे छात्रों को अपनी फीस भरने में, किताबें और स्टेशनरी खरीदने में व्यवधान हो रहा है और छात्रों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। ज्ञापन में मांग की गई हैं कि इन छात्रों की छात्रवृति जल्दी से जल्दी दे दी जाये। जिससे छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। प्रदर्शन और ज्ञापन देने में जो छात्र शामिल थे वे इस प्रकार है, संजय बरंडा, मांगीं लाल, अशोक, बाबू लाल, लक्ष्मण, मोहित, रोशन, ललित भूरिया, मुरारी लाल, आनन, विनोद, सीमा पारगी, भावना, पायल, बेंजा भगोरा, अमित मीणा, नरेश गुर्जर, लोकेश, हर्षिता, अमीषा, ललिता, रोहित, लबामा, चेतन, हारूल, जयंती लाल, परवीन बारगोट, गजेंद्र कुमार, विक्रम चंद, नरेश भील, कपिल मीणा, विजय कुमार, पुष्पेंद्र भील, यशवंत आदि। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि छात्रवृति जल्दी नहीं दी गई तो इस पर एक उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

13 सितम्बर, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सज्जाद जहीर का स्मृति दिवस

सज्जाद जहीर जिंदगी भर अपने मकसद के लिए लड़ते रहे

सिब्ते हसन

तरक्कीपसंद मुसन्निफीन के बानी सज्जाद जहीर की अचानक मौत ने एक अंजुमन, ऐसी प्यारी शख्सियत को हमारे दरमियान और उर्दू अदब के मैदान से उठा लिया है, जिसकी खिदमात जदीद उर्दू अदब की नश्व–ओ–नुमा (परवरिश) के सिलसिले में हमेशा याद रखी जाएंगी। ये नुक्ता काबिल–ए–गौर है कि उनका इंतिकाल ऐसे वक्त (13 सितम्बर, 1973) में हुआ, जब वो अफ्रीकी और एशियाई अदीबों की कॉन्फ्रेंस के लिए सोवियत संघ के अल्मा अता में शिरकत कर रहे थे। वाकिआ ये है कि अफ्रीका और एशिया के अदीबों का इत्तिहाद (मित्रता) और उनकी यक जेहती (एकजुटता) सज्जाद जहीर को हमेशा बेहद अजीज थी। सज्जाद जहीर लखनऊ हाई कोर्ट के चीफ जज सर सय्यद वजीर हसन के चौथे बेटे थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी से बीए पास किया और 1935 में बैरिस्टर बन गए। मगर उन्होंने न कभी वकालत की और न कोई मुलाजमत। बल्कि अपना तमाम वक्त सियासी और अदबी सरगर्मियों की नजर कर दिया। इंग्लिस्तान के कयाम के दौरान में उन्होंने साम्राजियत के खिलाफ तहरीकों में खुलकर हिस्सा लिया। जहां उनकी सोशलिज्म से दिलचस्पी पैदा हुई। सज्जाद जहीर बुनियादी तौर पर अदबी मिजाज रखते थे। चुनांचे लंदन में उनके तअल्लुकात आडेन, स्टीफन स्पेंडर, राल्फ फॉक्स और मुल्कराज आनंद जैसे अहम अदीबों और शायरों से हो गए थे। जो उन दिनों तरक्कीपसंद रुजहानात के लिए मशहूर थे।

सज्जाद जहीर फ्रांसीसी और अंग्रेजी जबानों पर पूरी महारत रखते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने ख्यालात का इजहार उर्दू ही में किया। इसलिए कि उन्हें उर्दू से बड़ा गहरा जज्बाती लगाव था। लंदन में उन्होंने अपना मशहूर–ओ–मारूफ नॉवेल 'लंदन की एक रात' लिख लिया था। जो आज भी वैसा ही ताजा और मकबूल है, जैसा कि अपने इब्तिदाई दौर में था। उस नॉवेल के बाद उन्होंने कई एक बहुत उम्दा अफसाने भी लिखे। उनका दूसरा बड़ा मारका आरा (असाधारण) काम कहानियों के उस संग्रह का संपादन और प्रकाशन था, जिसे 'अंगारे' के नाम से याद किया जाता है। शाए होते ही इस किताब ने पूरे मुल्क में एक तहलका मचा दिया था। ये कहानियां आज के दौर में बड़ी बे जरर (अहानिकर) सी मालूम होती हैं, लेकिन जिस जमाने में ये किताब छपकर सामने आई थी, उस वक्त के उर्दू पढ़ने वाले हमारे समाजी और अख्लाकी दोगलेपन के मुताल्लिक ऐसी खरी और सख्त तन्कीद पढ़ने के आदी नहीं थे। नतीजा ये निकला कि इस किताब पर रवायत–परस्तों ने बड़ी ले–दे की। यहां तक कि इस किताब के कहानी लिखने वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थीं। बिल आखिर यूपी गवर्मेंट ने इस किताब को जब्त कर लिया।

ये दौर पूरी दुनिया में सियासी, अख्लाकी और फिक्री ऐतबार से शदीद बोहरान (गहरे संकट) का वक्त था। हिटलर उन्हीं दिनों ताजा–ताजा जर्मनी की सत्ता में आया था और स्पेन की जम्हूरी और मुंतखिब हुकूमत का तख्ता जनरल फ्रेंको और उसके साथियों ने जर्मनी के नाजी और इटली की फासिस्ट कुव्वतों की मदद से उलट दिया था। जाहिर है कि यूरोप और एशिया के आजादी और जम्हूरियत पसंद फितरी तौर पर इस शख्सी आतंक की फैलती हुई बुराई से सख्त अस्त व्यस्त थे। चुनांचे उन्होंने दुनिया भर की तरक्कीपसंद अदबी कुव्वतों को मुनज्जम (संगठित) किया। ताकि फर्द की आजादी और उसके जम्हूरी हुकूक का अलम बलंद रखा जा सके। इस पस–ए–मंजर में सज्जाद जहीर और उनके साथियों ने ऐसे अदीबों की एक तंजीम की बुनियाद डाली, जो इंसानियत की माद्दी (भौतिक) और अक्ली सर बुलंदी (उत्थान) के हक में नबर्द आजमा (मुकाबला करने वाले) हो

सकते थे। 1936 में अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन कायम करने से पहले सज्जाद जहीर बर्र ए सगीर के तकरीबन तमाम मुमताज अहले इल्म और अदीबों और शायरों से मिले। और उनसे इस सिलसिले पर तबादला–ए–ख्याल किया। उनके इस ख्याल को अल्लामा इकबाल, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद, काजी अब्दुल गफ्फार, मिसेज सरोजिनी नायडू, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, मौलाना हसरत मोहानी, मौलान चिराग हसन 'हसरत', जोश मलीहाबादी और बहुत से दूसरे अदीबों ने बेहद सराहा। उनके अपने हम उम्रों ने उनकी भरपूर हिमायत की। 'अजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1936 में उर्दू के अजीम नॉवेल नवेस और अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद की सदारत में हुई। इस इजलास में सज्जाद जहीर को अंजुमन को जनरल सेक्रेटरी मुंतखिब किया गया और बहुत ही मुख्तसर अरसे में अंजुमन ने अपने आप को एक हद तक किसी ताकत के तौर पर साबित कर दिया और हमारे अदब में नई इकदार (मूल्यों) की आबयारी शुरू कर दी।

ताहम 1942 नजरबंदी के दौरान में सज्जाद जहीर ने सिराज मुबीन के काल्पनिक नाम से बहुत से अदबी मजामीन लिखे, जो अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन के तर्जुमानी रिसाले 'नया अदब' में शाए हुए। रिहाई के बाद वो बंबई चले गए। जहां उन्होंने 'कौमी जंग' के संपादन के फराइज अंजाम दिए। इसी दौरान में वो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुक्न मुंतखिब हुए। सज्जाद जहीर ने अपनी सियासी मसरूफियतों के बावजूद कभी उर्दू अदब और जुबान की खिदमत से गफलत नहीं बरती। ये खिदमत उन्होंने शुरू ही से खुद आईद कर्दा फर्ज (लागू किया हुआ कर्तव्य) के तौर पर अपनाई थी। और आखिर तक वो ये फर्ज निहायत जिम्मेदारी और लगन के साथ पूरा करते रहे। फन और अदब के बारे में सज्जाद जहीर के जज्बात निहायत गहरे और नाजुक थे। अदीबों के बारे में वो हमेशा इतने पुर–खुलूस और गर्म जोश (उदार और उत्साहपूर्ण) रहे कि वो अदीब भी, जो उनके सियासी मस्लक (राजनीतिक विचारधारा) से शदीद इख्तिलाफ रखते थे, न सिर्फ उनकी दोस्ती और उनकी रफाकत (संगत) का दम भरते थे, बल्कि हमेशा उनके अदबी मकासिद के बारे में खुले हाथों से सहयोग करते थे।

1947 के आखिर में सज्जाद जहीर पाकिस्तान चले आए थे। लेकिन 1951 में उन्हें रावलपिंडी साजिश के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद और मच्छ जेल की मशक्कत आमेज नजरबंदी के दौरान में सज्जाद जहीर ने दो निहायत वकीअ और पाएदार अदबी अहमियत की किताबें लिखीं। जिनमें एक फारसी के अजीम शायर हाफिज शीराजी की जिंदगी और शायरी का जाइजा और आलोचनात्मक अध्ययन है। इस किताब का नाम 'जिक्र–ए–हाफिज' है। दूसरी किताब 'रौशनाई' है, जो तरक्ढकीपसंद तहरीक की इब्तिदा और उसके फैलाव की तारीखढ भी है। और उन बेसरोपा इल्जामात द्धनिराधार आरोपऋ की मुदलिल तर्दीद द्धलगातार खंडनऋ भी, जो इस तहरीक पर थोड़े–थोड़े वक्फे द्धसमयऋ से आईद किए जाते रहे। सज्जाद जहीर को 1955 में मच्छ जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन फौरन ही उन्हें हिंदुस्तान भिजवा दिया गया।

सज्जाद जहीर पुरनवेस किस्म के अदीब नहीं थे। उन्होंने पच्चीस साला अदबी करियर में सिर्फ एक नॉवेल,

शेष पेज 14 पर...

2024 में भाजपा को मात देने का...

पेज 1 से जारी...

लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं?

जी20 की अध्यक्षता सभी देशों को बारी–बारी से मिलती रहती है। उसी सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत भारत को जी20 की अध्यक्षता का अवसर मिला। परंतु प्रधानमंत्री मोदी शेखी बघार रहे हैं कि यह अवसर उनकी कार्यकुशलता के कारण मिला।

डी. राजा ने कहा कि इस स्थिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आंध्रप्रदेश राज्य परिषद द्वारा आयोजित प्रचार बस यात्रा एक प्रेरणास्पद काम है। इस पृष्ठभूमि में आंध्र प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को तय करना है कि उन्हें उन पार्टियों के साथ जुड़ना है जो देश की धन–दौलत को निगल रही हैं और देश में सांप्रदायिक फूट पैदा कर रही हैं या उन पार्टियों के साथ जुड़ना है जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने, देश को बचाने और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की दिशा में काम कर रही हैं या फिर वे किसी बिल्ली की तरह ताक में हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान को बदलने तक की कोशिश की जा रही है। ऐसे में शासक पार्टियों और विपक्षी पार्टियों को देश को बचाने के लिए सही स्टैंड लेना होगा। कम्युनिस्टों ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनेक जुझारू संघर्ष किए और अनेक बलिदान किए हैं। उन्हें आज देश को और देश के संविधान एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा और जब तक मोदी को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंका जाता प्रचार बस यात्रा जारी रखनी होगी।

जन सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ. के. नारायणा ने कहा कि जब तक मोदी और जगन को सत्ता से उखाड़ा नहीं जाता, हम देश को और राज्य को नहीं बचा सकते। राज्य सरकार भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों को लाठियां दे रही है, परंतु उसे लाल चंदन के तस्करों का प्रतिरोध करने के लिए लाठियां देनी चाहिए थी। तिरुमल में मद्य निषेध है परंतु शराब घोटालों के मुखिया लोग टीटीडी गवर्निंग बॉडी में रह सकते है। क्या ऐसे लोग तिरुमल की पवित्रता की रक्षा कर सकते हैं? मोदी ने देश में अपने अनेक गोद लिए बेटे बना रखे हैं और उन्हें बचा रहे हैं, अतः वह स्वयं भी भ्रष्ट हैं। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव चिन्ह को जी20 के प्रतीक चिन्ह पर अंकित कराया जो अनुचित है। आज चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसियों के तौर पर नहीं। चंद्रयान की सफलता को वह अपनी सफलता के तौर पर पेश कर रहे हैं जबकि इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और पहले की उन सरकारों को जाता है जिन्होंने इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठन को स्थापित किया और बढ़ावा दिया। आज की परिस्थिति में जनता को मोदी, जगन और साथ ही केसीआर को भी चुनावों में पराजित करना होगा।

जन सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आंध्रप्रदेश राज्य सचिव के. रामकृष्णा ने कहा कि एक महीने तक चली बस यात्रा के दौरान पूरे राज्य में कहीं कोई विकास नजर नहीं आया। जगन के चार साल के कार्यकाल में राज्य में एक भी नई फैक्टरी नहीं लगी। वास्तविकता यह है कि अनेक उद्योग राज्य से बाहर चले गए हैं। जगन कूड़े–कचरे पर भी टैक्स लगा रहे हैं। वह कहते हैं कि रेत नीति को बदलेंगे। परंतु वह गलत बिलों के जरिये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। शराब की बिक्री में हर बोलत पर सौ रुपए ताडेपल्ली पैलेस को जा रहे हैं। चुनाव से पहले जगन ने वायदा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, परंतु पिछले चार साल में वह बिजली की दरों को 11 बार बढ़ा चुके है। नए–नए टैक्स थोपकर जगन अब तक राज्य के लोगों पर 50 हजार करोड़ रुपए का टैक्स–बोझ डाल चुके हैं।

जन सभा में पार्टी के राज्य सह–सचिव नागेश्वर राव एवं जे.वी. सत्यनारायण मूर्ति, पार्टी की राज्य कार्यकारिणी सदस्य अक्किनेनी वनजा, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावुलु वैंकेया, तमिलनाडु के भाकपा सह–सचिव वीरापांडयन आदि भी उपस्थित थे। पार्टी जिला सचिव मुरली ने अतिथियों का स्वागत और राज्य कार्यकारिणी सदस्य रामानायडू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। राज्य इप्टा के चंद्रनायक पैन्चैलैया, आर. पितचैया और नसीर ने क्रांतिकारी गीतों के साथ दर्शकों को भावविभोर कर दिया। मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी के राज्य सचिवमंडल पी. हरिनाथ रेड्डी ने की।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

किसान सभा की 'डेरा डालो–घेरा डालो' आंदोलन की धमकी

अनूपपुरः संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा अनूपपुर एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन व आमसभा आयोजित की गई। आमसभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष जनक राठौर ने कहा कि शहडोल संभाग व अनूपपुर जिले में 10 प्रतिशत से भी कम सिंचाई का रकबा है। पूरे प्रदेश में औसत सिंचाई 50 प्रतिशत है इसलिए किसानों ने शहडोल संभाग व अनूपपुर जिले में सिंचाई हेतु विशेष पैकेज दिया जाए व उद्वाहन सिंचाई योजना में सब्सिडी दी जाए। यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो किसान सभा सिंचाई सुविधाओं के लिए व प्रत्येक खेत में पानी उपलब्ध कराने के लिए जन आंदोलन करेगी।

सभा की जिला पंचायत सदस्य अंजू गौतम रैदास ने संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार ने न्यूनतम समर्थन लागत मूल्य का डेढ़ गुणा करने का लिखित आश्वासन देने के बाद भी सरकार ने पूरा दाम नहीं किया है।

उर्वरक व डीजल की कीमत बढ़ने के कारण कृषि उत्पाद की कीमत लगातार बढ़ रही है। सरकार ने दिल्ली के आंदोलन में लिखित आश्वासन देने के बाद भी इस मांग पर कार्यवाही नहीं की और ना ही किसानों का कर्ज माफ किया, इसलिए हम प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि कृषि उत्पादित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य का डेढ़ गुना किया जाए। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संयुक्त किसान मोर्चा शहडोल संभाग में डेरा डालो–घेरा डालो आंदोलन करेगी।

आमसभा को संतोष अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि शहडोल संभाग में कोयला व खनिज संपदा की भरमार है। सरकार संसाधनों का दोहन कर रही है किंतु यहां की आदिवासी व किसानों के हित में खनिज मद का पैसा खर्च नहीं किया जाता। इसलिए हम मांग करते हैं कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए व क्षतिग्रस्त नहरों व बांधो की मरम्मत कर सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए। यदि सरकार हमारी मांगों पर कार्यवाही नहीं करती तो पूरे संभाग के अंदर किसानों को संगठित कर जन आंदोलन किया जाएगा ।

आमसभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हीरालाल राठौर ने कहा कि हर्री बर्री भगतबाध गांव में उद्वाहन सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। लेकिन सरकार ने उक्त योजना में सब्सिडी बंद कर दी है। हमारी मांग है कि उक्त योजना में सब्सिडी चालू कर जिले के अंदर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए।

सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष मोहन राठौर ने विस्थापन वह मोजरबेयर में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि जिले के उद्योग व कल कारखानों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाए।

आमसभा को जनपद सदस्य चंद्र कुमार तिवारी, विवेक यादव, राउतराय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विजय विश्वकर्मा, ब्रजकिशोर साहू, रामलाल कोल, डीडी राठौर, सुरेश राठौर, मोतीलाल, जगदीश सिंह, विष्णु, राजाराम, दलपत केवट, मदन राठौर सहित सैंकड़ों किसान उपस्थित थे।

आमसभा के बाद एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायत बर्री, हर्री, सेंदुरी, मौहरी के जन समस्याओं व सिंचाई सुविधाओं के मांगों पर भी अविलंब कार्रवाई किए जाने का ज्ञापन दिया गया व माननीय प्रधानमंत्री के नाम व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

पेज 3 से जारी

इससे समझा जा सकता है कि आम लोगों के लिए महंगाई कितना बड़ा संकट है।

केंद्र सरकार ने 30 अगस्त से रसोई गैस की कीमत में 200 रु. प्रति सिलेंडर की कमी करने की घोषणा की है। भाजपा के समर्थक इसका उदाहरण देकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार महंगाई की समस्या के प्रति संवेदनशील है। मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी उस समय रसोई गैस का सिलेंडर 410 रु. में मिलता था। अब 200 रु. कटौती के बाद भी 950 रु. से अधिक में मिलता है। सिलेंडर का दाम यदि 410 रु. कर दे, उसके बाद ही सरकार अपनी संवेदनशीलता का दावा कर सकती है।

सीएमआईई के आर्थिक आउटलुक के अनुसार, महंगाई के कारण लोगों की उपभोक्ता धारणा में गिरावट आ रही है। सीएमआईई के उपभोक्ता भावना सूचकांक के प्रमुख घटकों में से एक घटक उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (जैसे कार, टीवी और अन्य घरेलू उपकरण) खरीदने का इरादा है। डेटा से पता चलता है कि यह इरादा पिछले 3 महीनों से ग्रामीण भारत के लिए नकारात्मक था और अब शहरी भारत के लिए भी शून्य से नीचे चला गया है। आमतौर पर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है और भविष्य के संबंध में भी आमतौर पर लोगों की समझ बढ़ रही है कि आमदनी में वृद्धि नहीं होगी।

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की असलियत

प्रधानमंत्री गाहे–बगाहे कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है।

भाजपा के राजस्थान में एक बड़े नेता पूर्व विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के संबंध में कहा कि यह अर्जुनराम मेघवाल भ्रष्टाचारी नम्बर एक है, इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मुकदमे चल रहे हैं। मैं मोदी को चिट्ठी लिखने वाला हूं .....भाई तुमने जिसको मंत्री बनाया है....कानून मंत्री। वह भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर था। तभी उसने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया था। गरीब और मजबूर लोगों को भी नहीं छोड़ा इसने और बचने के लिए राजनीति में आ गया। आज भी उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे है।

उन्होंने कहा, अर्जुनराम मेघवाल भ्रष्टाचार अफसर रहे है। उद्योग सेवा से लेकर कलेक्टर रहने तक अर्जुनराम मेघवाल ने कई भ्रष्टाचार किए। चुरू में कलेक्टर रहते सैनिक विधवा के कोटे से हाउसिंग बोर्ड से गलत लोगों को आवंटन किए। इसकी शिकायत हुई और एसीबी ने मामला दर्ज किया। इसकी दो बार जांच हुई, दबाव में एफआर पेश की। सेशन कोर्ट जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इस केस में दबाव बनाया जा रहा है।

अर्जुनराम मेघवाल केंद्र में मंत्री हैं। उनके खिलाफ भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाए हैं। परंतु केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच करने या उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से और भाजपा से निकालने के बजाय आरोप लगाने वाले विधायक कैलाश मेघवाल को ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया है।

यह है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की असलियत।

सज्जाद जहीर जिंदगी भर अपने...

पेज 13 से जारी...

चंद कहानियां और ड्रामे और जदली माद्दियत (द्वंद्वात्मक भौतिकवाद) पर एक किताबचा, हाफिज शीराजी की शायरी का तन्कीदी जाइजा, तरक्कीपसंद तहरीक की तारीख, नज्मों का एक मजमूआ और दो दर्जन से ज्यादा मजामीन लिखे। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने लिखा, जदीद उर्दू अदब पर उसके बड़े गहरे असरात पड़े हैं। उन्होंने अपना अदबी करियर बहैसियत अफसाना निगार के शुरू किया। लेकिन जल्द ही वो तन्कीद की तरफ निकल आए। और बिला शुब्हा (निरूसंदेह) उनके अफकार और ख्यालात की तर्जुमानी का यही सबसे अच्छा जरिया साबित हुआ। उर्दू तन्कीद की तारीख में उनके तन्कीदी मजामीन संग–ए–मील का दर्जा रखते हैं। उनके मजामीन से क्लासिकी और जदीद अदब की ताबीर और तन्कीद के लिए नई राहें खुलती हैं। जो सादगी उनकी शख्सियत का जुज्व थीं, वही उनके अदबी अस्लूब की खुसूसियत भी है। उन्होंने अदब की सिक्काबंद तरकीबें और भारी–भरकम अल्फाज अपने पढ़ने वालों को मुतास्सिर और खौफजदा करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए। वो किसी से अपनी जेहनी बरतरी मनवाने के कायल भी नहीं थे। वो दलीलों से आदमी को कायल जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी रिवायती, इल्मी अकड़फूं नहीं दिखाई। बहस–ओ–मुबाहिसे वो बड़े शान से करते थे। और अपनी सारी इल्मी कुव्वत सर्फ कर देते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी के जज्बात को मजरूह नहीं किया। वो तन्कीद बहुत सख्त करते थे, लेकिन न उनके दिल में किसी की तरफ से मैल होता था। न कभी निजी हमले करते थे। न कभी अपने मुखालिफ के बारे में सरपरस्ताना रवैया इख्तियार करते थे। फितरत ने उन्हें बड़ा मीठा मिजाज दिया था।

अम्र–ए–वाकिआ ये है कि वो हमारे दौर की सबसे ज्यादा पसंदीदा और प्यार किए जाने वाली शख्सियत थे। लोगों से मिलने–जुलने का उन्हें बेहद शौक था। और खास तौर से नौजवान लिखने वालों और जकी (बुद्धिमान) और जहीन नौजवानों से वो बड़े खुलूस से मिलते थे। न सिर्फ उनको बड़ी कुशादा पेशानी (उदारता) और खुश दिली (प्रसन्नता) के साथ खुश–आमदीद (स्वागत) कहते थे, बल्कि उनके मसाइल पर बड़ी तवज्जोह और गर्मजोशी से तबादला–ए–ख्याल करते थे। वो भी एक मुखलिस (सच्चा) दोस्त और उनके बराबर के साथी की हैसियत में, न किसी फतवे देनेवाले मुफ्ती की तरह। वो बड़े सब्र और सुकून के साथ दूसरों की गुफ्तुगू सुनते और कभी किसी मुलाकाती को उन्होंने हिरासां (निराश) करने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि उनका हर मुलाकाती उन्हें बड़े प्यार से 'बन्ने भाई' कहता था।

सज्जाद जहीर के अंदर अदबी तकरीबात की तंजीम और तर्तीब की बड़ी सलाहियतें थीं। मुख्तलिफ जुबानों और नस्ली गिरोहों से तअल्लुक रखने वाले अदीबों को एक प्लेटफार्म पर जमा करना और फिर उनको एक बड़ी तंजीम की लड़ी मे पिरो देना, बड़ा जान जोखिम का मरहला था। लेकिन सज्जाद जहीर ने यह काम निहायत खुश उस्लूबी (अच्छे प्रबंधन) से और हंसते–खेलते कर दिखाया। इस दौरान में न उन्होंने कभी उजलत पंसदी (आतुरता) दिखाई और न कभी किसी पर गुस्सा किया। और न ही उनके चेहरे पर कभी बेजारी (थकावट), थकावट और नागवारी का असरात देखने में आए। सज्जाद जहीर अदब और सियासत दोनों के बारे में सख्त जानिबदार थे। वो उम्र भर अपने मक्सूद–ए–नजर (उद्देश्य) के लिए रज्म आरा (योद्धा) रहे। और इस राह में उन्होंने बिला शुब्हा बहुत बड़ी कुर्बानियां दीं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, उन्होंने अपने दोस्तों और अजीजों पर कभी अपने नजरियात थोपने की कोशिश नहीं की। वो बड़े रौशन दिमाग इंसान होने के साथ–साथ सही मायनें में साहिब–ए–जौक और जमाल पसंद इंसान थे। इसलिए कि जिंदगी के हर हुस्न से उन्हें शदीद प्यार था। चाहे वो किसी रूप में क्यूं न हो ? और उसी शिद्दत के साथ वो लोगों की गुर्बत, बदहाली और जेहन पर पहरे बिठा देने से नफरत करते थे। वो मशरिकी और मगरिबी मूसिकी के बड़े दिल दादा (प्रशंसक) थे। फारसी, उर्दू और हिंदी शायरी को बेहद पसंद करते थे। वो उम्र भर इंसानों और इंसानियत की सर बुलंदी (उत्थान) के लिए बड़े खुलूस और रचाव के साथ जद्दोजहद करते रहे। किसी मौके पर भी उन्होंने किसी किस्म की तल्खी का शाइबा तक नहीं आने दिया। उर्दू अदब की तारीख में उनका नाम एक ऐसी जिंदगी बखश (जिंदगी देनेवाली) तहरीक के बानी की हैसियत से याद रखा जाएगा, जिसने इब्तिदा से अब तक आला तख्लीकी सलाहियतों वाली दो नस्लों को जन्म दिया है।

(उर्दू से हिंदी लिप्यंतरणः जाहिद खान/इशरत ग्वालियरी)

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 17 – 23 सितंबर, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 15.9.2023

भाजपा मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार: भाकपा

भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य और भाकपा संसदीय दल नेता, सांसद बिनोय विश्वम ने हैदराबाद में 10 सितंबर 2023 को कहा कि मणिपुर में विशिष्ट समुदायों के बीच दंगों का मुख्य कारण कॉर्पोरेट पक्षीय भाजपा नीत केंद्र और राज्य सरकार है, ये कॉर्पोरेट राष्ट्रीय संपत्ति और संसाधनों की लूट के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं।

बिनोय विश्वम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कटु आलोचना की जिन्होंने मणिपुर के संबंध में शेखी बघारते हुए कहा था कि पूरा देश मणिपुर की बहनों और माताओं के साथ है। प्रधानमंत्री अभी तक अग्निग्रस्त राज्य का दौरा करने के लिए समय नहीं निकाल सके। बिनोय विश्वम ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर के लोग भाजपा की संकीर्ण मानसिकता और धूर्त राजनीति का भारी नुकसान उठा रहे हैं। हम यह कहने में असमर्थ हैं कि कब यह हिंसा रुकेगी।

'मणिपुर–एक विश्लेषण' विषय पर आयोजित सम्मेलन में बिनोय विश्वम उद्घाटन भाषण दे रहे थे। सुरवरम सुधाकर रेड्डी, भाकपा के पूर्व महासचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। यह सम्मेलन दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार राघवचारी के जन्म वर्षगांठ समारोह के अवसर पर राघवचारी मेमोरियल ट्रस्ट, नीलम राजशेखर रेड्डी रिसर्च सेन्टर और चन्दर राजशेखर राव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

बिनोय विश्वम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि मणिपुर में समुदायों के बीच हिंसा की पृष्ठभूमि में उन्होंने दो बार राज्य का दौरा किया। दंगों के शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री ने कई देशों का दौरा किया लेकिन मणिपुर एक बार भी नहीं गए। आखिरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव बहस के जवाब में उन्होंने कहा कि मणिपुर भारत के साथ है। सभी को यह उम्मीद थी कि कम से कम संसद सत्र के बाद वे मणिपुर का दौरा करेंगे, लेकिन यह दौरा आज तक नहीं हुआ है।

बिनोय विश्वम ने आगे कहा कि समुदायों के बीच, द्वन्द्व मात्र आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से नहीं है। इसके पीछे मुख्य षडयंत्र कापोर्रेरेट का मुद्रा लोभ है।

आदिवासी बसावट वाले क्षेत्रों में बहुत से खनिज स्रोत हैं। अडानी की नजरें उन बहुमूल्य संसाधनों पर है। इस कारण से भाजपा ने क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा को शुरू किया है।

मैइती और कुकी अलग–अलग राहत कैम्पों में रह रहे हैं। ये कोई पुनर्वास कैम्प नहीं हैं लेकिन वे वहां अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वे अपने घर कब वापिस लौट सकेंगे। भाजपा 'बांटो और राज करो' की ब्रिटेन की नीति का अनुसरण कर रही है। वे अपने स्वार्थी हितों के लिए एक ओर मैइती के ऊपर हाथ रखते हैं तो दूसरी ओर कुकी के ऊपर। वर्तमान में दोनों ही समुदायों का भाजपा से विश्वास उठ गया है। लोग महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री दंगों को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। ऐसी हालत में लोगों के पास एकजुट होकर देश की अखंडता को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

बिनोय विश्वम ने यह भी कहा कि भाजपा की विध्वंसकारी नीतियों के खिलाफ 28 राजनीतिक पार्टियां एकजुट हुई हैं और उन्होंने एक फ्रंट

राम नरसिम्हा राव

बनाया है। उन्होंने इस फ्रंट का नाम ''इंडिया' रखा है। तत्काल ही भाजपा सरकार ने इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया। कई दशकों से देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन भाजपा ने एकतरफा निर्णय लेते हुए इसे बदलकर भारत कर दिया है। उन्होंने यह कदम लोगों का ध्यान उनकी समस्याओं से भटकाने के लिए किया है।

बिनोय विश्वम ने राघवचारी के बारे में बोलते हुए कहा कि वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वे प्रख्यात मार्क्सवादी पत्रकार थे। उन्होंने साम्यवादी पत्रकार के रूप में अथक रूप से आजीवन पार्टी पेपर विशाल आंध्रा के लिए काम किया। वे चिंतक, बुद्धिजीवी और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे।

सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने अपेन संबोधन में स्पष्ट किया कि मणिपुर में जहां डबल इंजन सरकार है, वहां सांप्रदायिक दंगे रुक नहीं सकेंगे। मणिपुर और म्यांमार और नेपाल सीमाओं के बीच कोई घेराबंदी नहीं है। उन्होंने बताया कि न तो वहां कोई परिवहन व्यवस्था है और न ही वहां कोई उद्योग। पहले भी द्वंद्व होते थे लेकिन वे व्यक्तियों के बीच थे परंतु अभी समुदायों के बीच द्वंद्व है। उन्होंने राघवचारी के संपादकीय की प्रशंसा में कहा कि वे काफी उत्कृष्ट और विश्लेषणात्मक होते थे। राघवचारी ने अपने संपादकीय लेखों में लिखा था कि भाजपा ने अपने गठन के शुरुआती दिनों में कहा था कि उनकी विचारधारा गांधीवादी समाजवाद की है। न तो गांधी ने कभी समाजवाद के बारे में कहा और न भाजपा ने कभी गांधी को अपना माना।

आईयूजे अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उनके नेतृत्व में पत्रकारों का एक प्रतिनिधि दल राज्य के मुख्य सचिव से पांच दिन पहले मिला था और उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की थी उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक निष्ठा होनी चाहिए। वाम और प्रगतिशील ताकतों को आगे आना चाहिए, समस्याओं का समाधान कर लोगों और राज्य को बचाना चाहिए।

डॉ. कुनामेनी रजनी ने डॉक्टरों की टीम के राहत कैम्पों के दौरे के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कैम्पों में न तो पर्याप्त दवाएं हैं और न ही भोजन की व्यवस्था। उन्होंने कैम्पों में गंभीर मरीज के चिकित्सा अभाव जैसे कि डायलेसिस के अभाव में 10 व्यक्तियों की मृत्यु पर चिंता व्यक्त की।

उप्र खेत मजदूर यूनियन के राज्य सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर

सोनभद्र: उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन के 1–3 अक्टूबर 2023 को ओबरा–सोनभद्र में होने वाले 14वें राज्य सम्मेलन के तैयारी समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष लल्लन राय की अध्यक्षता में बिजली कर्मचारी संघ कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर बिजली कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता व भाकपा के वरिष्ठ नेता राम अवध यादव ने अध्यक्ष लल्लन राय को 20,000 रुपये को चेक सौंपा। उप्र. बिजली कर्मचारी संघ के प्रान्तीय कार्यवाहक अध्यक्ष अजय सिंह ने भी बैठक को सम्बोधित किया। उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन के प्रान्तीय महासचिव फूलचन्द यादव ने बैठक में पूरे प्रदेश के आने वाले प्रतिनिधियों और राज्य सम्मेलन के तैयारी का विवरण बैठक में रखा। यूनियन के प्रान्तीय सचिव डॉ. आर. के. शर्मा ने जिले में सम्मेलन की तैयारी, कार्यकताओं, सम्मेलन स्थल, रैली, आमसभा का पूरा खाका बैठक में रखते हुए बैठक के संचालन का काम भी किया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.